हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1983

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 1983

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उततर	(7) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(7) 20
विभिनन विशयों का उठाया जाना– (i) पंजाब नै ानल बैंक पलवल मे धोख्झोबाजी संबंधी	(7) 23
(ii) श्रीमती करतार देवी, एम0एल0ए0 द्वारा सांपला निश्राम गृह मे एक महिला के अभिकथित बलात्कार के मामले मे जांच रिपोर्ट देने संबंधी	(7) 24
(iii) एंटी डिफैक ान (हरियाणा) बिल को अस्वीकार करने संबंधी	(7) 24

वाक आउट	(7) 26
वक्तव्य– उद्योग मंत्री द्वारा मिट्टी के तेल की दोहरी नीति संबंधी	(7) 26
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– बिलजी के बिलों को बढ़ा चढ़ा कर चार्ज करने संबंधी	(7) 28
वक्तव्य– सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(7) 32
श्रीमती करतार देवी, एम0एल0ए0 द्वारा सांपला विश्राम गृह मे एक महीला के अभिकथित बलात्कार के मामले मे जांच रिपोर्ट देने संबधी (पुनरारम्भ) बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(7) 37
वाक आउट	(7) 43
बिजनैसे एडवईजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट (पुनरारम्भ)	(7) 44
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(7) 44

वर्श 1982–83 के लिये सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान– (i) राज्य के राजस्वों पर प्रभावित व्यय के अनुमानों पर चर्चा (ii) अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(7) 45
वाक आउट	(7) 48
वर्श 1982–83 के लिये सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) का मतदान (पुनरारम्भ)	(7) 53

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Electricity Supplied to Agricultural Sector

***105. Shri Kitab Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the feeder wise number of hours for which electricity was supplied in the State for Agricultural sector daily during the period from 15-10-1982 to 15-11-1982?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

There are 737 feeders in the State which provide Electricity to Agricultural sector. The running of these feeders is logged daily on hourly basis at the sub stations. To compile the same, it has to be collected from 167; sub stations, scattered thorough out he state. There fore, collection of complete and correct information for the State as a whole is highly time consuming.

2. However, on the basis of date, available at the headquarters, board picture on the working of feeders, circle wise, in the State for the specified period is given below:-

Sr. No.	Name of Circle	District (s) covered	Average running hours per day (3 phase supply)
1	Ambala	Ambala	5.0
2	Kurukshertra	Kurukshertra	5.0
3	Karnal	Karnal	5.0
4	Delhi	Sonepat & Parts of Rohtak	8.0
5	Rohtak	Jind part of Rohtak & Sonepat	7.0

6	Hissar	Hissar & Sirsa	8.0
7	Bhiwani	Bhiwani & parts of Mohindergarh	8.5
8	Gurgaon	Gurgaon & parts of Mohindergarh	8.0
9	Faridabad	Faridabad & parts of Gurgaon	7.0

The above hours are for running feeders on 3 phase. Hower during remaining hours of the day, two phase supply has been given for lighting and general use.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, ने अपने सवाल के जवाब मे फीडर्ज को बिजली सप्लाई करने के बारे मे एक स्टेटमैंट टेबल पर रखी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सटेटमैंट मे जितने फीडर्ज बताए गए है, इनको कितनी बिजली मिलनी चाहिए थी, एकचुअल कितनी बिजली इनको सप्लाई की गई और यदि कम बिजली सप्लाई की गई तो उसके क्या कारण है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री किताब सिंह ने अपने सवाल मे 15 अक्तूबर से 15 नवम्बर तक एग्रीकल्चरल सैक्टर को फीडर वाईज बिजली सप्लाई करने के बारे मे पूछा है। उस दौरान 10 दिन बिजली

जनरे ान की पोजी ान बहुत4 खराब रही थी। उसका मेन कारण यह था कि पानीपत का एक थर्मल प्लांट किसी खराबी की वजह से बंद रहां इसके अलावा फरीदाबाद के एक प्लांट को छोड़ कर बाकी प्लांट इस दौरान एनुअल मंटीनैंस के लिये बंद थें अध्यख महोदय, जब बिजली की संप्लाई एक करोड़ यूनिट से नीचे चली जाती है तो यह समझते है कि बिजली की जनरे ान मे क्राइसिज आ गई है और जब बिजली की जनरे ान एक करोड़ यूनिट से ऊपर चली जाती है तो हम समझते है कि हमारी बिजली की जनरे ान की पोजी ान अच्छी है। उन दिनों बिजली की जनरे ान की पोजी ान एक करोड़ यूनिट से नीचे थी। 80–90 और 95 लाख यूनिटस से ऊपर चली जाती है तो हम एग्रीकल्चरल सैक्टर, इंडस्ट्रियल सैक्टर और डोमैस्टिक कन्जयूमर्ज के लिये पूरी बिजली सप्लीं करते हे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने सवाल के जवाब मे सर्किलवाइज फीडरों के निर्दिश्अ समय के लिये चलने का ब्यौरा दिया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बिजली की सप्लाई रैगुलर थी? कहीं ऐसा तो नही था कि अभी अधा घंटा के लिये तो कभी दस मिनट के लिये बिजली सप्लाई की गई हो ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे आपका भी काफी अच्छा तजुर्बा है और मैंबरज साहेबान भी जानते है कि बिजली की सप्लाई नौर्मली कंटीन्यूअस ही होती है।

बिजली सप्लाई सिस्टम मे जो इंट्र ंज होती है वह दो कराणो से होती हैं एक तो यह हे कि बी0बी0एम0बी0 से इंट्र ंज आ जाती है। दूसरा यह है कि वहां पर लोकली म ीनो मे किसी फाल्ट की वजह से इंट्र ंज आ जाती है। कई बार वहां पर म ीनों पर ज्यादा लोड बढ़ जाने के कारण म ीनों को बचाने के लिये उनको बंद करना पड़ता है इसलिये भी इंट्र ंज आ जाती है। ऐसा नही है कि कभी आधा घंटा और कभी 10 मिनट बिजली सप्लाई की गई हो। नौर्मली बिजली की सप्लर्ी कंटीन्यूअस हो रही है। जो हमने 5–7 और आठ घंटें की फिगर्ज दी है वह एवरेज फिगर्ज है। बिजली की सप्लर्ी इससे भी ज्यादा रही है। उस दौरान तीन फेस मे बिजली की सप्लर्ी थोड़ी कम थी लेकिन दो फेस मे इससे ज्यादा सप्लाई थी।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्टेटमैंट मे जो बिजली सप्लाई की एवरेज फिगर्ज दी गई है, क्या यह रूरल फीडर्ज की है, इनमे अर्बन फीडर्ज भी भाामिल है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, जो मेन सवाल पूछा गया है वह एग्रीकल्चरल सैक्टर के बारे मे पूछा गया है इसलिये यचे फिगर्ज एग्रीकल्चरल सैक्टर की सर्कलवाइज फिगर्ज है।

श्रीमती चंद्रवतीः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि बिजली सप्लाई मे जो इंट्र ांज होती है, क्या वह म ाोनों मे सब स्टैंडर्ड माल लगाने की वजह से होती है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, इस बारे मे सभी मालूम हो सकता है जब किसी इनडिविजुअल इंट्र ान की जांच करवाई जाये।

श्रीमती चंद्रावतीः फिर आप इनवैस्टीगेट क्यों नही करवातें ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड ने बाकायदा इस बात के लिये एक इनवैस्टीलगे ान सैल बनाया हुंआ हे जो ऐसी बातों को इनवेस्टीगेट करता है। इसके अलावा वह सैल बिजली के सारे सिस्टम को इम्प्रूव भी करता है। अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि आपोजी ान भी इस बात को जानती है और इस बात का इनको तजुर्बा भी है कि बिजली के सिस्टम को स्टैबलाइज करने मे बहुत टाईम लगता है। सारे 33 के0वी0 के सब स्टे ांज को 66 के0वी0 स्टे ोंज और 66 के0वी0 सब स्टे ांज को 120 के0वी0 स्टे ांज बनाने मे बहुत समय लगता है। यह एक दिन की बात नही है।

श्री देवी दोसः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब मे दिल्ली सर्कल को आठ घंटे बिजली सप्लाई करने के बारे मे

बताया है। उसमे सोनीपत का एरिया भी आ जाता है। इसके अलावा सोनीपत का एरिया रोहतक सर्कल मे भी बताया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सोनीपत के फीडर्ज को प्रति घंटा कितनी बिजली सप्लाई की जाती है और क्या पानीपत को सर्कल बनाने का विचार है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट दो सर्कलों मे फाल करता हूं इसलिये दोनो जगह सोनीपत मैन ान किया हुआ है। इसके अलावा सोनीपत को अभी सर्कल बनाने का सरकार का कोइ विचार नही है।

डा0 भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे जितने थर्मल प्लांटस है, उनकी बिजली की जनरे ान कपैसिटी कितनी है और एक्चुअप पावर जनरे ान कितनी है, अगर कपनैसिटी के मुताबिक पाव जनरे ान नही है तो उसके कया कारण है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, फरीदाबार का जो थर्मल प्लांट है, उसमे चार म ीने है। एक 15 एम0बी0ए0 की है और तीन 60–60 एम0बी0ए0 की है। इसी तरह से पानीपत थर्मल प्लांटस मे दो म ीने है, वे दोनो म ीने 110–110 एम0बी0ए0 की है। पानीपत के दोनों प्लांटस मे आज 85 परसैंअ बिजली प्रोडयूस हो रही है जो सारे हिन्दुस्तान मे सबसे ज्यादा है। इसके अलावा फरीदाबाद मे जो थर्मल प्लांटस है, उनमे

से जो 15 एस0डब्ल्यू0 की म ीन वाला प्लांट है वह बहुत अच्छी बिजली जनरेट कर रहा है। बाकि जो दूसरे थर्मल पलांटस जब से लगे है, उस समय से उनकी म ानें अच्छी तरह से स्टेबेलाइज नही हुई है, उसके लिये पिछले दिनों बिलजी बोर्ड ने काफी प्रयत्न किये है और उनमे इम्प्रूवमैंअ हुई है। आजकल किसी भी सैक्टर मे पावर कट नही है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया था कि अब कोई पावर कट नही हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी मे यह बात हे कि आज भी बिजली का ओवर लोड होने के कारण ट्रांसफारमर्स जल जाते है और जिस की वजह से टयूबवैल्ज को बिजली नही मिल पाती है ? सरकार ओवर लोड को इम्पूव करने के लिये क्या कुछ कर रही है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, आजकल बिजली की सप्लाई मे कोई कट नही है। लेकिन हमारे तीन चार स्पोस ऐसे हे, जैसे दादरी, नारायणगढ़ और सम्भालखा है, जहां परह म सिस्टम मे कुछ कंस्ट्रंटस की वजह से 24 घंटे बिजली सप्लाई नही कर सकते । हम बिजली सप्लाई सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिये चाहे वह ट्रांसफार्मर के जरिए हो और चाहे पावर सब स्टे ांज को अप ग्रेड करने से हो, लगातार कोि ा ा कर रहे है। इस काम के लिये पिछले साल भी पैसा बिजली बोर्ड को दिया गया था और इस साल भी काफी पैसा रखा है।

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, हमारे हरियाणा मे जितने भी थर्मल प्लांटस है उनमे से एक भी थर्मल प्लांट आन एन एवरेज फुल कपैसिटी का 40 परसैंट से ज्यादा बिजली जनरेट नही करता जबकि प्राइवेट थर्मल प्लांटस जैसे बिड़ला, टाटा के थर्मल प्लांटस है, वे 85 परसैंट आफ दि कपैसिटी बिजली जनरेट करते है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे थर्मल प्लांटस इतनी थोड़ी बिजली जनरेट क्यों करते है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इन्होंने जो 40 प्रति ात की बात कही है, यह ठीक है कि यह परफारमैंस अप टू दी मार्क नही है।

श्री मंगल सैन: क्या आप इसके कारण बतायेंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, यह भी मैं इनको बता देता हूं। इसमे छिपाने की कोई बात नही हैं बिजली की सप्लाई मे कई बार कोयले की कम सप्लाई के कारण भी दिक्कत आ जाती है, कई बार म ीनरी ठीक काम नही करती तो उस कारण प्लांटस को बंद करना पड़ता है। कई बार बिजली की ट्रिपिंग की वजह से दिक्कत आती है। जब म ीनरी मे कोई खराबी आ जाती है तो उस समय हमे ज्यादा दिक्कत आती है। म ीनरी की मेजर रिपेयर बी.एच.ई.एल. वाले करते है। इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते है कि बिजली की लगातार सप्लाई मे किस कारण दिक्कत आती है। पिछले तीन सालों का

जो प्लांट लोड फैक्टर रहा है वह मैं आपको बता देता हूं। ये फिगर 1981–82 तथा 83 की है। सन् 1983 के अंदर प्लांट लोड फैक्टर 65, 67, 61, 71, 66, 61, 65, 64, 63, 59 तथा 54 हैं सन् 1982 के अंदर प्लांट लोड 41, 31, 27, 27, 35, 47, 37, 40 तथा 43 रहा। इसी प्रकार से 1981 का प्लांट लोड फैक्टर 8, 9, 34, 24, 31, 32, 33 तथा 36 रहा है। इस प्रकार से लगातार कांस्टैंट इम्प्रूवमैंट हो रही है हमें उम्मीद है कि आल इण्डिया लैवल के के मुकाबले मे पर प्लांट लोड फैक्टर को हम बहुत जल्दी ही ऊपर ले जायेंगे।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमैंअ मे कहा है कि हम प्लांटस मे इम्प्रूवमैंट कर रहे है। इन्होकंने यह भी कहा है कि फरीदाबाद का एक यूनिट तो ठीक काम कर रहा है और बाकि के तीनों यूनिट जब से लगे है तब से ठीक काम नही कर रहे है। मैं इन से साफ तौर परयह पूछना चाहता हूं कि जो यूनिट ठीक काम नही कर रहे क्या उनकी म ाीनरी मे तो कमी नही है ? क्योंकि हो सकता है कि जब इन यूनिटस के अंदर म ाीनरी लगाई गई हो वह सब स्टेण्डर्ड है यदि म ाीनरी सब स्टैण्डर्ड है तो कया वे इस बात की इन्कवायरी करवाने के लिये तैया है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, इंकवायरी की कोई जरूरत नही है, क्योंकि ये यूनिटस ठीक काम कर रहे है। इंक्वायरी उस बात की हुआ करती है जिसके कारण न

पता हों वैसे मैं इनकी जानकारीी के लिये बताना चाहूंगा कि बिजली की ट्रिपिंग की वजह से भी खराबी हो जाती है। बिजली की ट्रिपिंग अकेले हरियाणा मे ही नही है। यह कीम हर स्टेट के हर पलांट मे है। जयों ज्यों ग्रैजुअली प्लांटस स्टैब्लाइज्ड होते जायेंगे, त्यों त्यों समस्या का समाधान होता जायेगा तथा प्लांट लोड फैक्टर बढ़ता जायेगा।

श्री मंगल सैनः क्या इस समस्या को खत्म होने मे 10–20 साल लगेंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अब तो यह समस्या तकरीबन खत्म हो चुकी है। हरियाणा के अंदर बिजली की सप्लाई दूसरी स्टेटों की अपेक्षा ठीक प्रकार से की जा रही है।

श्री किताब सिंहः स्पीकर सहाब मैंने कृशि क्षेत्र के बारे मे पूछा था। मैं इसी संबंध मे जानना चाहता हूं कि क्या ये फिगर्ज, फीडरवाइज जो दी गई है, ठीक है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, मैं इनकी बात को समझ गया। इनको ठीक प्रकार से पूछन नही आया। जो स्टेटमैंअ फीडर के संबंध मे 15–10–82 से 15–11–82 तक की दी है, यह समय क्राईसिज का होता है इनको मैं मोटे तौर पर पिछले साल के संबंध मे और इस साल के संबंध मे बताना चाहूंगा कि 20–11–82 से 12–12–82 तक बिजली पर कोइ कट नही लगाया गया । क्योंकि यह समय बीजाई का होता है।

हमने टयूबवैलों को प्रतिदिन लगातार 12 घंटे से 15 घंटे बिजली सप्लाई की है। 28–2–83 के बाद कोइ पावर कट नही है। हमने कई जगहों पर 24 घंटे लगातार बिजली दी है।

Elections to municipal Committees in the State

***107. @Shri Mangal Sein, Shri. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to hold Elections to Municipal Committees in the State; and

(b) if so, the time by which the election to Municipal Committees are likely to be held?

Minister of State for Local Government (Shri A.C. Chaudhry):

(a) Yes, Sir.

(b) As the date for holding these election has not been fixed the time by which the election will be held cannot be indicated at this state.

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब के 'ए' भाग मे कहा हे 'जी हां' और 'बी' भाग मे कहा है कि 'क्योंकि चुनाव कराये जाने की तिथि निि चत नही की गईण इस अवस्था मे यह नही बताया जा सकता कि चुनाव कब कराये जायेंगे।' इन्होंने कोई निि चत तिथि नही बताई। मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव करवाने मे इनको क्या रूकावट आ रही हे क्योंकि पिछले 14 सालों से नगर पालिकाओं के चुनाव नही हो रहे है ?

श्री ए0सी0 चौधरीः मेरे फाजिल दोस्त के मेन सवाल के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा थाि क क्या राजय मे नगरपालिकाओं

का चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसका जवाब मैंने दे दिया है कि 'जी हां' । दूसरा हिस्सा था कि यदि ऐसा है, तो नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक कराने की संभावना है । उस का उत्तर मैंने दिया है कि अभी तिथि नि चत नही बताई जा सकती है। सपीकर सहाब पहले तो चुनाव 1971 के सैंसीज के मुताबिक कराये जाने थे लेकिन बाद मे 1981 के सैंसीज के आंकड़े जून जुलाई तक आ चुके है। अब इनही के बेसिज पर चुनाव करवाये जाने चाहिये। मेरी इस बात से हाउस के सभी सदस्य सहमत होंगे।

मास्टर ि ाव प्र ाादः नई सैंसीज के मुताबिक जो वार्ड आदि बनने हे उन पर कब तक काम भाुरू हो जायेगा।

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, यह काम म्युनिस्पिल कमेटी का है। यदि मेरे बस मे या हमारे अधिकारियों के हाथ मे यह काम होता तो मैं तिथि बता सकता था। चूंकि अब यह काम म्यूनिसिपल कमेटी के स्टाफ ने करना हे, इसमे कुद समय तो लगेगा ही। इसलिये नि चत तिथि नही बताई जा सकती। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इस पर काम जितना जल्दी हो सकेगा, भाुरू करने की कोि ा ा करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः वार्ड बंदी और हल्के बंदी करके क्या ये हाउस को वि वास मे लेकर बता सकेंगे कि हम नगरपालिकाओं के चुनाव आगामी तीन सालों तक करवा देंगे ?

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, मैंने तो बड़ा सिम्पल सा सवाल पूछा था लेकिन इन्होंने बड़ा घिसा पिटा सा जवाब दे दिया। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि सैसिज की फिगर 1981 मे आई और इन के ऊपर म्यूनिसिपल स्टाफ ने काम करना था। स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी का तकाजा है कि चुनाव होने चाहिये। अरबन रिहैबिलिटैंटस के द्वारा फ्रैंचाईज को एक्सरसाईज करने का सवाल भी हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इस लाईट मे आपकी प्रोसैसिंग किस स्टेज पर है और इस दि ाा मे आपने क्या क्या पग उठा रखे है। ताकि कमेटियों के इलैक ान करवा सकें ? इस रास्ते मे क्या क्या रूकावटें है।

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी के तकाजे की बात को सामने रखने रखते हुए मैं यचह बताना चाहता हूं कि आफिस की फाइलें इस बात की बवाह है कि जब आप मिनिस्टर थे, उस वक्त म्यूनिसिपल एक्ट मे अमेंडमैंट करके आपने ये इलैक ान पोस्टपोन किये थे। इसके बाद 1977, 1978, 1979 और 1980 मे दोबारा अमैंडमैंट करके इलैक ान पोस्टपोन किये गये थे। इसके अलावा मेरे फाजिल दोस्त वे रूकावटें जानना चाहते है जो इलैक ान करवाने के रास्ते मे रूकावटें बनी हुई है। रूकावटें यह हे कि तकरीबन 24 म्यूनिसिपल कमेटी ज की पोलिटिकल पोर्टीज की तरु से और कई इंडिविजुअल्ज की तरफ से ये औब्लैक ान आते हरे है कि वार्ड बंदी गलत है, उसको ठीक किया जाये। बार्ड बंदी को ठीक करवाने के लिये म्यूनिसिपल

एडमिनिस्ट्रेटर्ज को ये आदे ा दिये गये हे कि जिस जिस लिमिट तक वे अपने वार्ड की हद बढ़ाना चाहते है, बढ़ा ले ताकि टैक्स की इवेजन और लीकेज खत्म की जा सके। म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर जो वार्ड बनाये जा सकते है, वे बनाये जाये।

Shrimati Chandravati: Sir, the Hob'ble Minister has not given a clear reply as to when the elections to the municipal committee are going to be held in the State? This should not be so, He is constantily giving the same reply that the date for holding the elections has nbot been foxed. He should give a definite reply.

Mr. Speaker: The Home Minister has expressed his difficulty in indicating the date.

चौधरी कुलबीर सिंह मालिकः स्पीकर साहब, क्या यह सत्य नही है कि सरकार जानबूझकर चुनाव नही करवा रही है और डे टू डे म्यूनिसिपल कमेटी की वर्किंग मे इंटरफीयर करती रहती है और मनमाने ढंग से काम करती है।

श्री ए0सी0 चौधरीः यह गलत बात है, इसमे कोई सच्चाइ नही है।

Shri Mangal Sein: This is no answer, Sir,

Shri A.C. Chaudhry: This is just a relevant answer.

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर सहाब, आउन एंड कंट्री पलानिंग विभाग का बहुत सा काम म्यूनिसिपल कमेटी के एरियें के

अंदर आता है। अगर मिनिस्टर साहब चुनाव करवाये बिना यह काम करवायेंगे तो यह सारा काम इरलीगल हो जायेंगा। (व्यवधान)

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक सैप्रेट डिपार्टमैंट है इस डिपार्टमैंट का मिनिस्टर भी अलग है और इस विभाग का म्यूनिसिपल कमेटीज के साथ कोई दखल नही है।

Shrimati Chandravati: Sir, may I know as to when are they going to hold the elections to Municipal committees and क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 15 याल से आप इलैक ान नही करवा रहे, क्या यह सरकार भाहर के लोगो को उनके हक से वंचित नही कर रही ? क्या इलैक ान होना उनका कांस्टीच्यू ानल अधिकार नही है?

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, मैं लोगों के हकूक की बात को मानता हूं। अगर किसी कारण से चुनाव नही हो सके, तो हमारे एम0एल0एज0 तो चुने हुए रिप्रैजेंटेटिव्ज है। ये अपने हकूक की हिफाजत तो कर सकते है ?

मास्टर ि ाव प्र ाादः स्पीकर साहब, 1981 मे हमारे एक्स मिनिस्टर श्री मांगे राम गुप्ता ने एलान किया था कि म्यूनिसिपल इलैक ान होंगे। क्या 1981 मे सैसिंज का सवाल उनके सामने नही था?

श्री ए0सी0 चौधरीः जहां तक एलान का ताल्लुक है, आपने देखा होगा हमने इलैक ान करवाने के लिये नोटिफीके ान जारी की थी कि हम 26 दिसम्बर, 1982 को इलैक ान कराने जा रहे है। इसके बाद हमारे सामने सिर्फ यही हरडल आई! उस वक्त सैंसिज की फिगर्ज हमारे पास तैयार थी। अगर उस वक्त हम 1971 के सैंसिज के बेस पर इलैक ान करवा देते तो 1971 के बाद जो लोग वोट के अधिकारी बने थे, उनको उनके राईट आफ वोट से डिपराइव करते। लिहाजा यही ठीक समझा गया कि 1981 की सैंसिज को आधार माना जाये।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, सरकार कुछ भाहरों मे म्यूनिसिपल कारपोरे ान बाने जा रही है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रोहतक भाहर को म्यूनिसिपल कारपोरे ान बनाने का मामला उनके विचाराधीन है ?

श्री ए0सी0 चौधरीः किसी भी भाहर मे म्यूनिसिलप कारपोरे ान बनाने के लिये पहली रिक्वीजिट यह है कि दो लाख के ऊपर की आबादी वाले भाहर को कसीडर किया जा सकता है और इस नार्म के मुताबिक भाायद फरीदाबाद कम्पलैक्स को छोड़ कर कोई दूसरी म्यूनिसिपल कमेटी ऐसी नही है जो इस क्राईटेरियें को पूरा करती हो। अगर मेरे साथी चाहते है तो सरकार इस पर गौर कर सकती है।

Purchase of Tarpaulins

***118. @Shri Kanwal Singh, Ch. Kulbir Singh Malik:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Haryana State Agriculture Marketing Board purchased tarpaulins worth more than rupees ninety lacs during the period from the month of July, 1979 to day;

(b) if so, whether it is also a fact that the quality of these aaid tarpaulins was found to be substandard; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative the action taken or proposed to be taken in the matter?

Agriculture Minister (Chaudhri Surender Singh):

(a) No. However, the Market Committees int he State purchased tarpaulines worth Rs. 8783447/- during the period from July, 1979 upto 28th Feb. 1983.

(b) The matter is under enquiry by the Vigilance Departement for enquiry.

(c) The matter is unde renquiry by the Vigilence Department. However, 29 Secretaries, of the Market Committees, have been placed under suspension after preliminary enquiry by the Agricultural Marketing Board. Department action has been intiated by the Agricultural Marketing Board. Action is also being taken against the other officials involved in these purchases.

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, आप मंत्री जी का जवाब देख लीजिए, इन्होंने सवाल के पार्ट (बी) को इग्नोर करके उसका वेग सा जबाब दिया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन 29 सैक्रेटरीज को इन्होंने सस्पैंड किया हे, इनके खिलाफ क्या क्या प्राईमार फेसाई केसिज है ? दूसरी बात यह है कि तिरपालों को 15 रूपये के रेट की बजाये 25 रूपये के रेट से खरीदा है, क्या यह रेट ठीक है और 29 मार्किट कमेटियों मे जो परचेजिंग हुई है, क्या यह ठीक हुई है? परचेजिंग के लिये जो नार्म्ज बनये हुए है क्या उनको इस केस मे फोलों किया गया है?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः टरपोलाइंज की परचेजिंग का प्रोसीजन दूसरी आइटम्ज से अलग नही है। यह बात दूरूस्त है कि टरपोलाइंज की ि ाकयत हमाने पास आई है। सारी मार्किट कमेटी ज ने यह खरीद की और हम महसूस करते है कि वास्तव मे इस खरीद मे कुछ इररैगुलैरिटीज हुई है। यह सारा केस विजिलैंस डिपार्टमैंट को इंक्वायरी के लिये भेज दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सवाल के भाग (बी) मे पूछा गया है

"If so,k whether it is also a fact what the quality of these said tarpaulins was found to be substandard."

इस का जवाब मंत्री जी ने यह दिया–

"The entire matter has been referred to the Vigilance Deparment for enquiry."

इलको जो ि ाकायत थी, उसमे सपैंसिफिक एलीगे ान थे कि तरपालों की क्वालिटी घटिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका जवाब इन्होंने क्यों नही दिया ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि ि ाकायत मे एलीगे ांज भी हे कि मैटीरियल सब स्टेंडर्ड है और दूसरे एलीगे ांज भी है परचेजिंग प्रोसैस ठीक से फौलों नही किया गया है। हम महसूस करते है कि न कुछ किसी न किसी लैवल पर मार्किट कमेटियों द्वारा की परचेजिंग मे गड़बड़ है। जब हमें भाक हुआ तो हमने सारे का सारा मामला विजिलैंस को इंक्वायरी के लिये भेज दिया।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं वजीर साहब को कहना चाहता हूं कि आखिर तक इस मामले पर डटे रहे। ऐसा ना हो कि किसी के प्रै ार मे आ जाये। स्पीकर साहब, इन्होंने अपने जवाब मे कबूल किया है कि जो ि ाकायत आई है, उस मे माल सब स्टैंडर्ड को ि ाकायत है। इस मे यह भी गलीगे ान है कि नार्म की फौलो नही किया गया, इसीलिये इस के स को विजिलैंस डिपार्टमैंट को इंक्वायरी के लिये भेजा है। स्पीकर साहब, इन्होंने सवाल के पार्ट (सी) के जवाब मे फरमाया है–

"The matte ris under enqiury be the Vigilance Department. However, 29 Secretaries, of the Market Committees, have been placed under suspension after preliminary enquiry by the Agricultural Marketing Board."

ये 29 आफि ियल कौन कौन है, इनके खिलाफ क्या क्या चार्जिज हे, क्या आप उनके नाम बतायेंगे जो इस केस मे इन्वाल्वड है और जो इंवाल्वड है उनके खिलाफ आपने क्या एक ान प्रपोज किया है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मार्किट कमेटी के लिये किसी भी आईटम की प्रचेज करने के लिये आफिसर्ज की अलग अलग स्टेजिज पर अलग अलग डियूटीज है। मसला अकाउंटैंट, रैजिडैंट आडिट आफिसर एग्जैक्टिव आफिसर कम सैक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर इन सभी के खिलाफ जिसकी जितनी जिम्मेवारी हे और जो भी उसके गलती की है, सब के खिलाफ एक ान ले रहे है।

श्रीमती चंद्रावतीः मंत्री महोदय, बतायेंगे कि क्या यह प्रचेज अप्रूव हुई थी ? जिन्होंने प्रचेज की है उनके क्या क्या नाम है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मार्किट कमेटी मे प्रचेज का सवाल हे उसका बहुत सिम्पल तरीका है। पचास रूपये तक की प्रचेज सैक्रेटरी मार्किट कमेटी कर लेता है। हर मार्किट कमेटी की अलग अलग बजट है बजट भी कुछ एक कमेटीज का दस दस हजार का है लेकिन प्रचेज ज्यादा पेसे की हुई है। किसानों की और आढ़तियों की मांग को मददेनज5र रखते

हुए मार्किट कमेटिज ने बोर्ड से डिस्कस करके यह सारा मामला तय किया ।

एक सदस्यः क्या किसी की जिम्मेदारी फिक्स की है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत साफ साफ कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर अकाउंटेंट इंकल्यूडिंग एग्जैक्टिव आफिसर तक की अलग अलग जिम्मेदारी है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 20 हजार रूपये से अधिक के तिरपाल किस किस मार्किट कमेटी ने खरीदे है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः लाडवा, घरोंडा, रादौर, चीका, पेहवा, कैथल, तरावड़ी, असंध, निसिंग, ढांड, करनाल, नीलोखेड़ी, इसराना, इंद्री, भाहबाद, पुंडरी, गुहला, इस्मायलाबाद, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, छछरौली, यमुनानगर, गुड़गांवा, सोहना और बरवाला आदि आदि।

श्री देवी दासः मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया है कि सन् 1979 से 28 फरवरी, 1983 तक 8783447 रूपये के तिरपाल खरीदे है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये एक ही फर्म से खरीदे है या अलग अलग फर्मों से खरीदे है ? अगर एक ही फर्म से खरीदे है तो अलग अलग मार्किट कमेटी ने कितने कितने रूपये के तिरपाल खरीदे है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, किसने कहां से माल खरीदा, यह इंफर्मे ान नही आई है, वह तो विजिनैस डिपार्टमैंट देगा। लगभग 13 फर्मे हे जिनसे तरपाल खरीदे है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि विजिलैंस की इंक्वायरी रिपोर्ट कब तक तक मिल जायेगी ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः इन डयू कोर्स आफ टाईम मिल जायेगी।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मार्किट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर 20 हजार रूपये तक की प्रचेज कर सकता है और क्या यह विद इन रूल्ज परमिसीबल है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय एडमिनिस्ट्रेटर मार्किट कमेटी के लिये कितनी ही प्रचेज कर सकता है लेकिन प्रचेज पोसिजर मे फर्क है। अगर प्रचेज बीस हजार से नीचे हो तो कुटे ान ले सकता है और ऊपर की हो तो टैंडर इंवायट कर सकता है।

चौधरी साहब सिंह सैनीः मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस केस मे क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर भीर इन्वाल्वड है, अगर इन्वाल्वड है तो अब तक क्या कर्यावाही हुई है और नही हुई है तो क्या करने जा रहे है?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः जितनी मार्किट कमेटीज के एडिमिनिस्ट्रैटर एस0डी0एम0 है, वे सभी इसमे इन्वाल्वड है।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, हमारे एक भी सवाल का जवाब नही आ रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लैटर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वह अपने लैवल पर लिखल है। मार्किट कमेटी, बोर्ड और कारपोरे ांज की अपनी फंक ानिंग होती है। बोर्ड आफ डायरेक्टरज होता है उन्होंने अपने लैवल पर चिट्ठी लिखल है न चीफ मिनिस्टर ने न मिनिस्टर ने और न ही सैक्रटेरियट मे बैठे हुए किसी सैक्रेटरीज से बात करके खरीदे है। सरकार की इसम कोई दखल अंदाजी नही है। (विघ्न) (इस समय कई सदस्य सप्लीमैंट्री पूछने के लिये खड़े हुए)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, इस सवाल पर हाफ एन आवर डिस्क ान होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह डिमांड कर ले कि क्या हर मैंबर को चार चार सप्लीमेंटरी करने का मौका दिया जाये? यदि ऐसा करेंगे तो क्वै चनज और भी कम आनसन हो सकेंगे। मैं पहले ही दो दो सप्लीमेंटरी करने का मैंबर्ज को मौका दे रहा हूं लेकिन उसके बावजूद भी पूरे क्व चनज आनसर नही हो पाते । इस सवाल पर मैं समझता हूं कि काफी सप्लीमैंटरी हो गये है और फरदर डिस्क ान की जरूरत नही है। नैक्सट क्वै चन।

Construction of Dams for the State

***122. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) whether any Dams are at present under construction or are proposed to be constructed int he near future for the benefit of the State;

(b) if som, details thereof togetherwith the details of the time since when such Dams are under constructionor the period withing which construction thereof is likely to be started and completed; and

(c) the details of the benefits which are likely to accure to the State by such Dams?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) No Dam is at present unde rconstruction. Thein Dam on river Ravi and Kishau Dam on river Yamuna are proposed to be constructed. Thein Dam will tbe constructed by the State of Punjab and Kishau Dam will be constructed by the State of U.P. The State of Haryana stands to benefit from these inter State Projects.

A Diversion Dam is proposed to be constructed across river Sutlej under Nathpa Jhakri Project for the diversion of water though tunnels for the generation of power.

(b) The construction of Dams has not so far been started. The dates of completion cannot, therefore, be forecast at this stage.

(c) Haryana will be able to get its full share of 3-5 m.a.f. of surplus Ravi Beas water after the construction of Thein Dam Haryana' claim on sharing of power for this Dam is under the consideration of Union Government.

Haryana's share in Kishau Dam storage has not so far been finally determined.

500 crore units of power are estimated to be generated under Nathpa Jhakri Hydro electric Projects. Haryana will get 42 % share out of this power.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सहाब, मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए इस सवाल के (ग) भाग मे बताया कि थीन डैम के निर्माण उपरांत हरियाणा को रावी व्याय के सरप्लस पानी का 3. 5 एम0ए0एफ0 हिस्सा पूरा मिल जायेगा तथा इस डैम से पैदा होने वाली बिजली के बंटवारे पर हरियाणा का कलेम भारस सरकार के विचाराधीन है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कलेम तो हमारा एस्टैबलि ाड है लेकिन जो क्वांटम आफ भोयर विचाराधीन है वह कितना है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः हमारे कलेम तो मान गये है लेकिन determination of share is still under consideration of the Union Government.

श्री मंगल सैनः मंत्री महोदय ने सवाल के पार्ट (सी) के जवाब मे यह लिखा है कि

"Haryana will be able to get its full share of 3.5 m.a.f. of surplus Ravi Beas water after the construction of Thein Dam....."

क्या यह बात सही हे कि थीन डैम बन जाने के बाद आपको उसमे हिस्सा मिल जायेगा? दूसरी, मैं एक बौर बात पूछना चाहता हूं। कल ही हिमाचल विधान सभा, ि ामला मे यह बात आयी है कि नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट को सैंट्रल गवर्नमैंट से एप्रूवल नही मिली है। जब इस प्रोजैक्ट को एप्रूवल ही नही मिली है। जब इस प्रोजैक्ट को एप्रूवल ही नही मिली है तो आप कैसे यह एंटीसिपेट कर रहे हैक कि आप उससे बैनिफिट डिराईव करेंगे?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक नाथपा झापड़ी प्रोजैक्ट का ताल्लुक है, इस प्रौजैक अकी टैक्नीकल एप्रूवल बहुत पहले से ही गवर्नमैंट आफ इंडिया से मिल चुकी है। फाइनैं ीयल क्लीयरैंस मिलनी बाकी है जिसमे यह देखना है कि कौन सी स्टेट कितने पैसा लगायेगी और उसका प्रबंध वह कैसे करेगी। प्लानिंग कमी ान मे यह थौरोली डिस्कस हो चुका है। तकरीबन वहां पर भी सारी बातों का फैसला हो गया है सिर्फ फैसले की अनाउंसमैंट की इंतजार है। जहां तक थीन डैम का संबंधह ै, अध्यक्ष महोदय, जब तक थीन डैम नही बनता 0.

617 एम0ए0एफ0 पानी जो आजकल पाकिस्तान को बेकार जा रहा है यह जाता रहेगा, लेकिन इस डैम के बन जाने के बाद यह पानी भी अवेलेबल हो जायेगा।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने पार्ट (ए) के जवाब मे यह कहा कि "No damis at present under construction....." इस सवाल मे डैम की कोइ डैफीनी ान तो नही दी गयी है। महेन्द्रगढ़ मे साहबी नदी पर डैम बन रहा है और भी कई छोटे छोटे डैम बन रहे है। हरियाणा मे जो छोटे छोट डैम बन रहे है, स्पीकर साहब उसके बारे मे कोई इंफर्मे ान नही दी गयी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सवाल तो सारे डैम्ज के बारे मे थात्र इसमे जो हरियाणा मे छोटे छोटे डैम्ज बन हरे है , उनके बारे मे जवाब क्यों नही आया ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो कहा गया है कि कोइ डैम फिलहाल अंडर कंस्ट्रक ान नही है, यह ठीक है क्योंकि अभी तो थीन डैम की जो इंफा स्ट्रक्चर है वह ही बनी है जिनमे रैजीडै ीयल कालोनीज और रोड़ज वगैरा बन चुकी है ओर इसके अलावा इसका कुछ पार्ट आफ दी टनल भी कम्पलीट हो चुका है। नाथपा झांकड़ी मे भी रोड़ज तकरीबन कम्पलीट हो चुकी है और रैजीडैं ीयल कालोनीज लगभब बन चुकी है। (व्यवधान व भाोर) यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि वहां पर कोइ काम हुआ ही नही है। हमने नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट के लिये हिमाचल सरकार को पैसा भी

दिया है। जहां तक छोटे छोट अरदर्न डैम्ज का ताल्लुक है, हरियाणा मते केवल एक जगह ही नही, ऐसे डेम कई जगह बन रहे होंगे। इन्होंने उनके बारे मे स्पैसिफिकली पूछा नही है, अगर पूछेंगे तो बता दूंगा। इसका मतलब यह तो नही कि मैं हर छोटे बड़े डैम के बारे मे इंफर्मेशन सप्लाई कर दूं।

श्री नेकी रामः अध्यक्ष महोदय, हमने अब तक हिमाचल सरकार को 50 लाख रूपये नाथपा झागड़ी प्रोजैक्ट के लिये दिये है।

श्री सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, अखबर मे आज यह खबरी आयी है कि कल ही हिमाचल विधान सभा मे एक मंत्री महोदय ने यह कहा है कि नथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट के बारे मे अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमैंट से कोई पैकज या एग्रीमैंट नही हुआ है। इस बारे मे हरियाणा सरकार की क्या पोजीशन ओर स्टैंड है कि एग्रीमैंट हुआ है या नही हुआ है अगर नही हुआ है तो क्या वैसे ही आश्वासन से यह रूपया देते जा रहे है कि एग्रीमैंट हो जायेगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी तीन चार अखबार पढ़े है। मैंने कहीं ऐसी बात नही पढ़ी जैसे इन्होंने बतायी है कि एग्रीमैंट हुआ ही नही है। उसमे सिर्फ इतनी बात है कि फाइनैंशियल क्लीयरैंस नही हुआ है। एग्रीमैंट वगैरा

सब कुछ हो चुका है। भोयर भी डिटरमिन हो चुका है। कौन यह प्रौजैक्ट बनायेगा ऐसी सारे चीजे भी फानैलाईज हो चुकी है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, नाथपा झाकड़ी मे जीन चार किलो मीटर आगे एक स्थान है करचम वांगटू, वहां पर बहुत अच्छा फाल अवेलेबल है, ओर मेरा ख्याल हे कि वहा से कम से कम 600–700 मैगावाट बिजली पैदा हो सकती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर भी प्रौजैक्ट बनाने के लिये एग्जामिन करने पर विचार करेगी ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र हिमाचल प्रदे ा मे है। सारा हिल्ली रिजन है और वहां पर बर्फ पड़ती रहती है। इसलिये वहां पर बहुत से फाल्ज अवेलेबज है। इस बारे मे पोजी ान यह है कि अगर हिमाचल गवर्नमैंट हमारे से इस बारे मे समझौता करना चाहे तो हम बाचतीत कर सकते है।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय थीन डैम की कोइ स्पैसिफिक डेट या कोई लगभग समय निर्धारित करेंगे कि इस समय तक बन कर अव य तैयार हो जायेगा ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इस डैम के बारे मे मैडम प्राइम मिनिसटर ने जो क्लीयरैंस बहुत दिनों से पैंडिंग थी यह भारत सरकार की तरफ से दे दी थी लेकिन अभी जो इसकी टनल्ज वगैरा बनती है, उनककी टैक्नीकल एप्रूवल

और सैक ान पैंडिंग है! वह जब तक नही हो जाती, इसकी एबसैंस मे कोई टाईम लिमिट फिक्स नही की जा सकती।

श्रीमती चंद्रावतीः कुछ महीने या साल या सैंचुरी, कुछ तो बता सकते है! (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, गलत बात कहने से कोई फायदा नही है। जैसे मैंने बताया है इस बारे मे एग्जैक्टली कुछ नही कहा जा सकता कि थीन डैम कितने समय के अंदर बन जायेगा।

श्री हीरा नंद आर्यः मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे यह लिखा है कि थीन डैम के निर्माण उपरांत हरियाणा को राबी ब्यास के सरप्लस पानी का 3.5 एम0ए0एफ0 हिस्सा पूरा मिल जायेगा। भाायद 1964 मे यह डैम बनाने का प्रस्ताव किया गया था। उस समय 60 करोड़ इसकी कीमत एस्टीमेट की गयी थी लेकिन अब इसकी कास्ट 700 करोड़ रूपये हो चुकी है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब से जो एग्रीमैंट हुआ था, उसके मुताबिक कब तक यह कम्पलीट हो जायेगा और क्या इसके कम्पलीट होने के बाद मेक हमें 3.5 एम0ए0एफ0 पानी का हिस्सा मिलना भाुरू होगा या उससे पहले? (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, मैं भी आई0पी0एस0 रहा हूं। मैं भी यह समझता हूं कि इस बारे मे गलत बात कहने से कुछ

फायदा नही होगा। कोइ यह बात पक्के तौर पर नही कह सकता कि यह डैम कब तक कम्पलीट हो जायेगा।

श्री हीरा नंद आर्यः कंस्ट्रक ान के बारे मे नही बता सकते तो न सही लेकिन यह तो बता दें क्या जब यह डैम पूरा हो जायेगा तो हमें 3.5 एम0ए0एफ0 पूरा पानी मिलेगा या नही?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः बिल्कुल पूरा हिस्सा मिलेगा। न मिलने का या कम मिलने का तो सवाल ही नही है। जो पानी आजकल पाकिस्तान को वैसे ही जा रहा है फिर वह भी अवेलेबल होगा और वह प्रोपो र्निटली सारी पार्टनर स्टेटस को मिल जायेगा।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट का एग्रीमैंट हुआ पड़ा है। उसकी फाईनैं गियल क्लीयरैंस मिलनी बाकी है। आप भी आई0पी0एम0 रहे है। यह यहां पर होकर आये थे। रीवर के अप–स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम काफी फाल्ज अवेलेबल है। वहां पर इंजीनियर्ज ने हमें यह बताया कि अगर वहां पर साथ ही 3–4 किलो मीटर पर जो करचम बांगटू का फाल अवेलेबल है, उसका भी समझौता हरियाणा के साथ हो जाये तो इंफ्रा–स्ट्रक्चर का काफी खर्चा जो आलरेडी हो रहा है, वह बच जायेगा। मगर उसके लिये पंजाब वालों के साथ उनकी बातचीत हो रही है। जो इंफ्रा–स्ट्रक्चर नाथपा झांकड़ी मे अवेलेबल होगा, उसी के साथ

आप दूसरा प्रोजैक्ट भी बना सकते हो। क्या हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदे ा के साथ करचम वांगटू पर भी प्रोजैक्ट बनाने के बार मे बातचीत करने के लिये तैयार है या नही ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, पंजाब हमारी सिस्टर स्टेट है इसलिये इस बारे मे ज्यादा कहना अच्छा नही होगा। पंजाब स्टेट इस प्रोजैक्ट (नाथपा झाकड़ी) मे भोयर करने मे बहुत इच्छुक थी लेकिन हरियाणा इसमे कामयाब हो गया । यह हमारे मुख्य मंत्री जी की सबसे बड़ी सफलता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे कोई नैचुरली रिवर नही है जिससे हाइड्रो बिजली पैदा की जा सके। अगर हरियाणा को कोई दूसरा चांस मिलेगा तो इसका भी हम पूरा फायदा उठायेंगे। उसके लिये हरियाणा सरकार पूरी तरह से जागरूक है। यह सबसे बढ़िया प्रोजैक्ट है।

House Rent Allowance

***142. Shri Hira Nand Arya:** Will a Minister of Finance be pleased to state whether there is any difference between the house rent allowance being givben to the Government employees serving in the rural areas and urban areas; if so, the basis on which different rates have been prescribed?

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar): House rent allowence is admissible only infew “towns”. The

dividing line originally was towns having a population of 25000 and above. Consequently most towns too did not qualify for house rent allowance being paid to employees stationed there. As villages had smaller population still, there was no ques ion of grant of house rent allowance in villages. The saME situation prevails today and it has been reported that no villages in the State had a population of 25000 or more as per the 1981 census. There is accordingly no quesiton of there being any difference in the rates pre cribed for rural and urban areas for the purpose.

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, देहात मे जो सरकारी मुलाजिम रहते है उनको भी मकान की आव यकता होती है और वे भी मकान का किराया देते है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि केवल भाहरों मे हाउस रैंट देना, क्या देहात मे रहने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नही है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, अगर किसी देहात की आबादी पच्चीस हजार या उससे ज्यादा होगी तो हम अव य वहां पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को हाउस रैंट देंगे।

श्रीमती चंद्रावतीः मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गांव मे जो सरकारी मुलाजिम रहते है क्या वे आसमान की छत के नीचे रहते है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, जो सवाल पूछा गया है वह इन आर्डर ही नही है। सवाल यह था कि क्या

भाहरों तथा गांवों मे नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले मकान किराया भत्ते के रेट्स मे कोई अंतर है। यदि हां तो कि आधार पर भिन्न रेट्स को निर्धारित किया गया है । इस बारे मे मेरा कहना यह है कि चाहे वह देहात है या भाहर है, जहां की आबादी पच्चीस हजारा से कम है वहां पर कर्मचारियों को हाउस रैंट नही मिलता है। इसमे टाउंज और देहात का कोई डिफरैंस नही है।

चौधरी ओम प्रका ाः मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1981 की जनगनणा मे झज्जर की कई कालोनीज को क्या झज्जर भाहर मे भाामिल नही किया गया है और क्या इस बारे मे सरकार के पास कोई ि ाकायत आई है, अगर हां तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, झज्जर भाहर की पंच्चीस हजार की आबादी न होते हुए भी जनता रूल मे जो उस वक्त के फाइनैंस मिनिस्टर थे उन्होंने कायदे के खिलाफ झज्जर भाहर को 'बी' क्लास घोशित कर दिया था। अब उसको विदड्रा कर लिया गया।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, सवाल मे (मूल प्र न) यह पूछा गया था कि भाहर और देहात के हाउस रैंट मे क्या फर्क है। मंत्री जी ने उसके जवाब मे बताया है कि देहात मे हाउस रैट नही मिलता है इसलिये फर्क का सवाल नही रहता है।

मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध मे कोई रिप्रिजैंटे ान आई है देहात मे रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी आवास की दिक्कत आती है, इसलिये उन्हे हाउस रैंट प्रोवाइड किया जाये?

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, सरकार की पोलिसी है कि जहां की आबादी पच्चीस हजार या उससे ज्यादा है वहां पर सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जायेगा। 1981 के सैंसिज के मुताबिक हरियाणा मे कोई गांव ऐसा नही है जिसकी आबादी पच्चीस हजारा हो, इसलिये देहात मे हाउस रैंट मिलने का प्र ान ही पैदा नही होता।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नही आया है। झज्जर मे रहने वाले या गांव मे रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की तरफ से कि उन को भी मकान भत्ता मिलना चाहिए इस बारे मे कोई रिप्रिजैंटे ान सरकार को मिली है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः इस बारे मे कोइ कम्पलैंट नही आई।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, जब झज्जर की आबादी पच्चीस हजार से कम थी तब तो वहां पर हाउस रैंट दे दिया गया लेनिक जब उस फैसिलिटी को विदड्रा कर लिया गया है क्या उस दौरान वहां के एम्पलाईज ने हाउस रैंट अलाउंस ड्रा किया था ?

चौधरी कटार सिंह छोकरः जी हां। हाउस रैंट लेते रहे थे।

श्री भागी रामः मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कर्मचारियो की पोलिटीकल आदमियों से जान पहचान होती है वह उनसे मिलकर अपना ट्रांसफर भाहरों मे करवा लेते है क्योंकि भाहरों मे हाउस रैंट मिलता है ? गांवों मे कोइ भी कर्मचारी नही जाना चाहता क्योंकि वहां पर हाउस रैंट नही मिलता मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या गांवों मे रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी हाउस रैंट देने पर रकार विचार करेगी जिससे कि उन कर्मचारियों की हौसलाअफजाई हो सके?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, किराया देने का उद्दे य यह है कि पच्चीस हजार की आबादी वाले भाहरों मे कौस्टली मकान मिलते है, किराया ज्यादा देना पड़ता है। यह कोई कंसीड्रे ान नही है कि जो एम्पलाईज गांव मे पोस्ट किये जायें वे इसलिये न जायें कि वहां पर हाउस रैंट नही मिलता।

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, पच्चीस हजारया उससे ज्यादा आबादी वाले भाहरों मे सरकारी कर्मचारियों को सी0सी0ए0 और हाउस रैंट दिया जाता है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पच्चीस हजार से कम आबादी वाले भाहरों या

कस्बों मे रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक कमी को पूरा करने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, सी0सी0ए0 तो एक लाख की आबादी वाले भाहरों मे मिलता है। आर्थिक कमी कोई नही होती है। सरकार की जो इस समय पालिसी है वह पच्चीस हजार या उससे अधिक आबादी वाले भाहरों मे मकान किराया भत्ता देने की है।

श्री निहाल सिंहः कुछ ऐसे भी मुलाजिम होंगे जो डाक्टर मंगल सैन की केटेगिरी के है जिनका कोई घर नही है (हंसी)। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे कर्मचारियों को भी हाउस रैंट के बारे मे सरकार विचार करेगी?

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये मेरे बड़े भाुभ चिंतक है। मुझे भी मकान चाहिए। दो चारपाई वाला नही तो एक चारपाई वाला तो अव य चाहिए (हंसी)।

श्री अध्यक्षः अबक्वै चन आवर खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये

तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Building of Marketing Board at Rania town

***168. Shri Bhagi Ram:** Will be Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the building of Marketying Board at Rania twon in District Sirsa is under construction; if so, the date on which its construction was started; and

(b) whether it is a fact that the work on the said building remained suspended; if so, the reasons therefor?

कृशि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) जी नही। परन्तु नई अनाज मण्डी रानियां मे मार्किट कमेटी के लिये कार्यालय कम विश्राम गृह भवन का निर्माण हरियाणा राज्य कृशि विपणन मण्डल द्वारा मार्च, 1979 मे आरम्भ किया गया था।

(ख) जी हां ठेकेदार की लापरवाही तथा ढील के कारण कार्य स्थगित रहा है।

Soil Testing Laboratory

***157. Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to shift the Soil Testing Laboratory from Mohindergarh to someother place in the State; and if so, the reasons therefor?

कृशि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह): जी हां। महेन्द्रगढ़ मे हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय, हिसार द्वारा अधिक परिश्कृत क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोग ाला स्थापित कर दिये जाने के कारण दोहरे

कार्य को बचाने के उदे य से महेन्द्रगढ़ मे स्थित कृशि विभाग की उप मण्डलीय भूमि परिक्षण प्रयोग ाला को कालका मे स्थानांतरण करने के आदे ा दिये गये है।

School Building at Sampla

***163. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whetehr it is a fact that the bu9lding of the Government Hisgh School, Sampla (Hassangarh Constituency) is a dilapidated condition; and

(b) if so, the place where the children studying in the above said school are likely to be shifted?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) जी हां।

(ख) कक्षाओं को अस्थाई रूप मे तीन अलग अलग संस्थाओं मे चलाने के प्रबंध पहले ही किये जा चुके है, क्योंकि सारे स्कूल के लिये योग्य तथा पर्याप्त किरायें का भवन तत्काल उपलब्ध नही था।

Cooperative Sugar Mill at Kaithal

***276. Chaudhri Nar Singh:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a cooperative Sugar Mill at Kaithal; if so, the time by which the afore said Mill is likely to be set up?

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): जी हां। कैथल सहकारी चीनी मिल, कैथल के लिये लाइसैंस लेने का प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा जा रहा है। इस अवस्था मे कोई मियाद नही दी जा सकती है।

Parity to Haryana Government aided schools

***289. master Shiv Prashad:** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether the Government took any decision on 12-6-74 to effect that all aided schools under the Sewcurity of Services Act, 1971, will be treated at per with the Government Schools in the matter of pay, D.A. & other facilities provided to them; and

(b) if so, whether that decision is being implemented and if not, the reasons thereof?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) जी नही, किन्तु सरकारने 12—6—74 को कुछ वि ोश अधिनियमों की संरक्षण (हरियाणा एडिड

स्कूल्ज) सेवा सुरक्षाएक्ट 1971 के अंतर्गत की थी जो कि अराजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों पर लागू होती है।

(ख) उपरोक्त नियमों की पालना अराजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों मे कर्मचारियों के नियुक्ति कर्ताओं द्वारी की जानी है।

Purchase of Wool from Sheep Owners

***273. Shri Man Phool Singh:** will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state whether there is any proposal unde consideration of the Government to purchase wool from such owners of the sheep as have been given loan for the purchase and rearing of sheep?

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (सरदार हरपाल सिंह): लौहारू तथा हिसार मे दो ऊन श्रेणीकरण तथा विपणन केन्द्र कार्य कर रहे है जोकि भेड़ पालकों, जिसमे ऋण प्राप्तकर्ता भेड़ पालक भाामिल है, से ऊन खरीदते है।

Som Nadi

***319. Chaudhri Bhagmal:** Will tbe Minister for Irrigation and Power pleased to state—

(a) wheterh it is a fact that Som Nadi has changed its course during the rainy season of the year 1982 in cojsituuency Sadhaura;

(b) if so, the details of points hwere tha fore said Nadi changed its course togetherwith the names of the villages affected as a result thereof;

(c) whether any 'Bundhs' are proposed to be constructed to check the change int he course of the said Nadi; if so, the number thereof; and

(d) whether the construction work has beenstarted on the Budhs ar referred to in part (c) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिसंह सुरजेवाला):

(क) हां।

(ख) सोम नदी ने अपना रूक्ष सढ़ौरा चुनाव क्षेत्र मे ग्राम खानुवाला के सामने बदलाा जिसके कारण ग्राम चिन्तपुर, लोपो, हरौली और खानुवाला को नुक्सान पहुंचा।

(ग) हां। बाढ़ ऋतु मे गांव की आबादी तथा कृशि भूमि की सुरक्षा हेतू एक मिट्टी के बांध का पांच तंग आड़ों (Buddy spurs) सहित निर्माण किया गया।

(घ) मौजूदा बांध को मजबूत करने का प्रस्ताव है तथा यदि आव यकता हुई तो कुछ ठोकरे लगाई जायेंगी और जांच पडताल तथा स्कीम की अनुमोदन के उपरांत कार्य आरम्भ भी किया जायेगा।

विभिन्ना विशयों का उठाया जाना

(i) पंजाब नै ानल बैंक पलवल मे घोखेबाजी संबंधी

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं ान मों ान पलवल के पंजाब नै ानल बैंक मे 6 लाख 10 हजार रूपये के फरौड के बारे मे दिया था कि वहां पर बड़ा भारी फरौड हुआ है। इस केस मे प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन इंवाल्वड है। इसी कारण से मुझे यह मामला यहां पर रैफर करना पड़ा हैं इस बारे मे आपने हमें कुछ बताया नही है।

श्री अध्यक्षः वह मामला अंडर कंसिड्रे ान है। उस बारे मे मैने रिपोर्ट भी मंगवायी है।

(ii) श्रीमती करतार देवी एम0एल0ए0 द्वारा सांपला विश्राम गृह मे एक महिला के अभिकथित बलात्कार के मामले मे जांच रिपोर्ट देने संबंधी।

डा0 भीम सिंह दहिया: श्रीमती करतार देवी जी ने किसी मामले मे यहां पर रिपोर्ट देनी थी, इस बारे मे मैंने आपसे पिछले हफ्ते बात भी की थी। आपने कहा था कि आप इस बारे मे हाउस मते बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैने श्रीमती करतार देवी जी से बात की थी। यह रेप का मामला है। वह इस बारे मे जांच करने मे हेसीटेट कर हरी थी। उन्होंने कहा कि आप इस काम के लिये किसी और आदमी को नियुक्त कर दीजिये।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, आप पहले ही इस बात को कह देते।

श्री अध्यक्ष: दहिया साहब, मैं तो सभी मैंबर साहेबान का आदर करता हूं। ठीक है I willdepute some one else.

(iii) एंटी डिफैक ान (हरियाणा) बिल को अस्वीकार करने संबंधी।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, मैं एंटी डिफैक ान बिल के बारे मे कुछ कहना चाहती हूं। (ाोर)

Mr. Speaker: It has been disallowed on the gound that the object underlying the proposed Bill can injstifiably be achieved though an amendment of the Representation of Peoples Act, 1951.....(Interrptions)

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, एंटी डिफैक्शन बिल को रि–कंसिडर करने के बारे मे आपने हमें एक आ वासन दिया था.....(विघ्न).... स्पीकर साहब, मेहरबानी करके मेरे बिल को रिजैक्ट न करे क्योंकि अगर आपने अपनी रूलिंग दे दी तो यह अपने आप ही रिजैक्ट हो जायेगा। इस लिये मेरीर आप से प्रार्थना है कि यह बड़ा अहम बिल है। आप अपनी रूलिंग रिजर्व रखे और इस बिल को रि–कंसिडर करे, हमे इसी मे सबर रखेंगे।

Mr. Speaker: Please take your seat. I am coming to that.

श्री मंगल सैनः स्पीकर सहाब, क्या आप कोई रूलिंग पढ़ रहे है?

श्री अध्यक्षः हा, मैं ऐंटी डिफेक ान बिल के बारे मे अपनी रूंलिग दे रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि रूलिंग देने से पहले आप हमें बोलने का मौका दे दे।

श्री अध्यक्षः मैंने आपको अपने चैंम्बर मे सुना था, आप आये भी थे। वहां यह फैसला हुआ था कि एल0आर0 और एडवोकट जनरल की इस बारे मे राय ली जाये। मैंने उनसे कंसल्ट करके ही यह रूलिंग देने का फैसला किया है। (ाोर एवं व्यवधान) Now let me give my ruling. (Interruptions)

The object underlying the proposed Bill can justifiably be achieved thourgh an amendment of the representation of peoples Act, 19514 and/or the constitution of India and/or by enactment of Central Legislation in this regard. In terms of entery 37, List II Schedule VII of the Constitutiion of India, the competence of the State Legislature in this regard bas been been made subject ot the provision of law made by the recommendation of the Election Commission of India and in the circumstances, it would not be appropriate to discuss it here.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे मे हमारे भी अरागुमैंटस सुन ले। मैं यह आपसे रिक्वैक्ट करूंगा कि आप अपनी रूलिंग को रिजर्व रखे। कई स्टेट असैम्बलीज मे यह बिल पास हो चुका है जैसे तामिलनाडु मे यह बिल पास हो चुका है और कर्नाटक मे पास करने जा रहे है। हम स्पीकर साहब, इस बारे मे आपको प्रमाण देंगे (ाोर व व्यवधान)

आवाजें: स्पीकर सहाब, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

(इस समय बहुत सारे सदस्य उठकर बोलने लगे)

श्री मंगल सैनः स्पीकर सहाब, आपकी रूलिंग का सिर्फ इसी प्रदे ा मे नही बल्कि सारे दे ा मे इसका प्रभाव पड़ने वारला है और हरियाणा की विधान सभा पवर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। एक करोड़ 31 लाख हरियाणा की जनता आपके फैसले के बारे मे क्यासोचगी ? इसके बड़ी पणिाम निकलेंगे। अच्छा होता अगर आप हमं बुलाकर यह कह देते कि एल0आर0 और एडवोकेट

जनरल ने हमें यह सलाह दी है, उसके बार आपके क्या विचार है। स्पीकर साहब आपको पता ही है कि ये 36 चुनकर आये थे और आज 58 बैठे है। (ाोर व व्यवधान) अगर यह बिल लागू होता तो ऐसा नही हो सकता था।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, बात यह है कि इलैक ान कमि ान की सिफारि ा पनर भारत सरकार ने यह मैटरसीज किया हुआ है, वह इस पर सोच विचार कर रही है। इन हालात मे मै यह नही समझता कि यहां पर इस बिल पर विचार किया जाता ।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, आप अपनी रूलिंग तो रिजर्व रखसकते है।

श्री अध्यक्षः अगर मैं इस पर रूलिंग रिजर्व रखूंगा तो आपके बिल का क्या बनेगा।

श्रीमती चंद्रावतीः अगर आप आज्ञा दें तो हम इस पर डिसक ान कर सकते है और अगले सैशन तक आप अपनी रूलिंग रिजर्व रख सकते है।

श्री अध्यक्षः बहन जी, आप भी तो अगले सै ान मे इसका दोबारा नोटिस दे सकते है।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, हमारी आपसे बार बार प्रार्थना है कि आप अपनी रूलिंग मत दीजिये । आप इसको रिजर्व रखिये।

श्री अध्यक्षः बहन जी, बात ऐसी है कि अब मै इसको रिजर्व नही रख सकता क्योंकि मैं इसकी सूचना आपको भेज चुका हूं और यह अनाउंस भी हो चुकी है।

वाक आउट

श्रीमती चंद्रावतीः मुझे तो आपके सचिवालय से यह पता चला है कि यह बिल एडमिट हो चुका है। अगर आप हमारी रिक्वैस्ट हो नी मानते तो हम एज एक प्रोटैस्ट वाक आउट कर जायेंगे।

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठियें मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं।

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गये)

वक्तव्य

उद्योग मंत्री द्वारा मिट्टी के तेल की दोहरी नीति संबधी

श्री अध्यक्षः दिनांक 11–3–83 को श्री राम विलास भार्मा, एम0एल00 की ध्यानाकर्शध सूचना नम्बर 18 का जवाब देने

के लिये मिनिसटर साहब ने आज का वायदा किया था। वे कृपया अपनी स्टेटमैंट दे।

Industries Minister (Shri Lachhman Singh): The Government ofg India has introduced dual pricing system for Kerosene Oil w.e.f. 14th/15th February, 1983 (midnight). Under the new schemes, the Government of India will continue to make allocationof Kerosene Oil on the basis of 1982-83 monthly allocations. of the quantity so allocated, 70% willbe supplied for distribution at the subsidized prices and the blance 30% will be distributed at notified non subsidized prices. As a result of this dual pricing policy, the State Government has taken the following defisions:-

(i) The quantum of Kerosene Oil to be supplied per month against each ration card to dopmestic unsers shallbe decided by each District Magistrate taking into account the availability of Kerosene Oil in his district. This quantum shall be distributed in the ratio of 70:30 of subsidized and non-subsidized Kerosene Oil.

(ii) Non-subsidizd 30% Kerosine Oil is entirely optional and no domestic cosumer can be forced to buy it alongwith the subsidized 70% K.Oil.

(iii) The domestic consumers having L.P.G. connections shall be supplied non-subsidized Kerosene Oil only. Their ration cards are being stamped to that they may draw their supplies of non-subsidized Kerosene Oil, as per decision of the Government.

(iv) Since 100% Kerosene Oil will be supplied against ration cards/permits, the demand of all commercial establishments/bulk consumers (other than domestic consumer) like hotels, restaurants, dhabas, private hospitals etc. would be met from 30% non-subsidized Kerosene Oil. However, the demand of the students canteens, Govt. hospitals and orphanages would be met like dome tic constumers in the ratio of 70:30 of subsidiized and non-subsidized Kerosene Oil respextively.

The Ex-dept prices of Kerosenwe Oil are fixed by the Government of India and the wholwsale/retail sale prices of Kerosene Oil both subsidized and non-subsidized are fixed by the District Magistrate in each District. These prices very from ploace to place depending upon the road distance involved. Retail prices of Kerosene Oil of subsidized and non-subsidized presently in vogue in the State are as under:-

(i) Subsidized K.Oil = Rs. 1.84 to Rs. 1.99 per litre.

(ii) Non-subsidized K. Oil = Rs. 3.24 to Rs. 3.37 per litre.

Against the State allocation of 10930 Kiloliters, the total upliftment in the monthe of February, 1983 was 9280 Kilolitres out of which 5600 Kiloliters was received upto 15th February, 1983.

The upliftment of Kerosene Oil from 16th February, 1983 onwards i.e. date of intruduction of new scheme has been as under:-

All figures in K. Litres

		Subsidized Oil	Non-subsidized Oil
(i)	From 16th Feb., 1983 to 28th Feb., 1983	3260	420
(ii)	From 1st March, 1983 to 7th March, 1983	1258	694

It needs to be mentioned that it is the first time that duel pricing system of Kerosene Oil is being ried in the country. Some difficulties are bound to occur at the initial stages. Even then Kerosene Oil is available in the State and is being issued to the consumers though the retail outlets. It willnot be correct to say that neither subsidized nosr non-subsidized Kerosene Oil is available in the State. I would like to inform the House that there is a regular flow of subsidized and non-subsidized Kerosene Oil in the State from the three depots of the Oil Companies located at Ambala, Hissar and Shakurbasti. The State Government will keep a strict vigil for proper supply of Kerosene Oil in time. We are already in touch with the Oil Comanies to ensure that there does not remain any scarcity of Kerosene Oil in the State.

We are very much keen to safegaurd the interestes of the poorer sections of the society and this dual pricing policy is intended to protect the interests of this section primarily. It is in this light, and keeping in view the policy of

the Central Government, that 70% of the requireent of the domestict consumers is being met at the subsized price. Further, insructions have already been issued by the State Government that strict action should be taken promptly against adopt holders to cancel/suspend licences and against negligent officials wherever any case of administration. I would like to assure the House that the State Government is fully alive to the situation and would not spare any efforts to keep up the supply of Kerosene Oil in adequate quantity in differenct districts of the State.

श्री राम विलास भार्माः स्पीकर साहब, मेरे काल अटैं ान मो ान के जवाब मे मंत्री जी ने यह कहा है कि गरीबों की जरूरत को ध्यान मे रखेंगे। मेरा सवाल यह है कि सबसीडाइज्ड और खुला कैरोसीन एक ही दुकान से बिकता है। ऐसा होने से ब्लैक मार्किटिंग के बहुत चांसिज रहते है। क्या सबसीडाइज्ड और खुला कैरोसीन आयल अलग अलग दुकानों के थ्रू लोगों को दिया जायेगा ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, यह पालिसी अभी अभी लागू हुई है। इसको अभी तजुरबे के तौर पर ट्राई किया जा रहा है। अगर इसमे कोई मु कल नजर आएगी तो दोबारा भी विचार किया जा सकता है।

श्री राम विलास भार्माः स्पीकर साहब, यह जो दोहरी नीति बनी है इससे सबसे ज्यादा मार हरिजना वस्तियों, मजदूर कालोनियों ओर गांव के लोगो को पड़ी है। क्या मंत्री जी के

विचाराधीन कोई ऐसी पालिसी है कि रा ान के तेल की मात्रा को बड़ा दिया जाये?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, इस पालिसी के लागू होने से पहले जितना तेल जिलों मे कंज्यूम किया जाता था, वहां उतनी ही सप्लाई जारी है। हर कंज्यूमर को 1.85 रू0 से लेकर 1. 90 रू0 पर लिटर के हिसाब से तेल मिलेगा।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

बिजली के बिलों को बढ़ा चढ़ा कर चार्ज करने संबंधी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे चौधरी वीरेन्द्र सिंह, एम0एल0ए0 की ओर से इलैक्ट्रीसिटी के हाउली एग्जाग्रेटिड बिल चार्ज करने के बारे मे एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस मिला है। मैं इसे एडैमिट करता हूं। अग चौधरी वीरेनद्र सिंह जी अपना मो ान पढ़ दे और मंत्री जी अपनी स्टेटमैंट दे दे।

Shri Verender Singh: I though this Calling Attention notice want to draw the attention of the Government towards a matter of urgent Bass Azamshahpur, Bass Khurd, Badchpur, Mohlla, Puthi and Badhala fall under Sub-division of Mundhal and haryan State Electricity Board. To extract money from innocent farmers and other consumers highly exaggerated bills have been issued by the office of S.D.O Mundhal for the month of January, Those who consumed the

electricity upto billing of rupees 15 to 20 in the past have been billed in the range of Rs. 600 to 800. Those who greese the palm of the concerned officer/official their bills are rectified. About ten thousand consumers hae been affected by this system of corrupt billing. A sample list of few of the consumers indicating the amount of billing with their respective meter Number isbeing attached. This has caused a great resentment in the whole sub-division among the consumers and people are feeling very much agitated. The matter has acquired an urgent public importance and hence, I call the attention of Irrigation and Power Minister to make a statement on the floor of the House.

List of Bass Tehsil Hansi District Hissar.

S. No.	Name	Meter No.	Amount	Remarks
1	2	3	4	5
1	Ranmal S/o Beg Chand	B.S.195	617.20	
2	Chatar Sinngh	B.S.268	616.75	
3	Muthura	B.S.465	607.60	
4	Bhim Singh	B.S.324	623.50	
5	Mange Ram	B.S.516	618.00	
6	Rup Chand	B.S.360	612.15	
7	Dene Ram	B.S.355	643.50	

8	Balmat Singh	B.S.619	630.50	
9	Jagbir Singh	B.S.526	613.95	
10	Dharam Pal	B.S.90	607.50	
11	Mange Ram	B.S.153	625.85	
12	Balwant Singh	B.S.367	710.00	
13	Tek Chand	B.S.336	707.00	
14	Rattan Singh	B.S.413	619.00	
15	Bharat Singh	B.S.412	605.00	
16	Mahabir Singh	B.S.558	701.00	
17	Bhagwan	B.S.469	617.10	
18	Rajbir	B.S.588	618.55	
19	Tara Chand	B.S.443	615.30	
20	Banarshi Datt	B.S.541	631.82	
21	Budh Ram	B.S.539	612.66	
22	Umed Singh	B.S.612	608.50	
23	Nafe Singh	B.S.429	700.00	
24	Risal Singh	B.S.500	611.80	
25	Nafe Singh	B.S.544	631.00	
26	Jogi Ram	B.S.222	636.00	

27	Ramesh Chand	B.S.333	616.40	
28	Bhal Singh	B.S.377	612.75	
29	Kashi Ram	B.S.269	606.24	
30	Sube Ram	B.S.272	619.00	
31	Debi Ram	B.S.322	689.00	
32	Ramfal	B.S.528	700.00	
33	Rati Ram	B.S.464	612.60	
34	Jogi Ram	B.S.531	622.50	
35	Bhale Ram	B.S.438	611.70	
36	Puran Chand	B.S.181	640.24	
37	Pirthi Singh	B.S.466	609.30	
38	Ujir Singh	B.S.451	619.00	
39	Munshi Ram	B.S.499	614.00	
40	Munshi Ram	B.S.442	606.00	
41	Nafe Singh	B.S.477	643.05	
42	Neki Ram	B.S.353	629.82	
43	Manful Singh	B.S.418	705.54	
44	Bhal Singh	B.S.377	612.75	
45	Nathu Ram	B.S.125	622.40	

46	Ram Chander	B.S.414	593.64	
47	Balmat Singh	B.S.282	610.90	
48	Rangbir Singh	B.S.409	609.00	
49	Ram Kumar	B.S.223	614.00	
50	Richpal	B.S.431	621.50	
51	Darya Singh	B.S.143	612.81	
52	Jora Singh	B.S.498	610.90	
53	Surpa	B.S.	616.00	
54	Tek Ram	B.S.352	608.55	
55	Rathu Ram	B.S.436	629.03	
56	Mashudi	B.S.305	653.18	
57	Ramfal	B.S.508	618.10	
58	Jage Ram	B.S.509	614.50	
59	Mange Ram	B.S.475	705.00	
60	Bhak Chand	B.S.517	631.30	
61	Balwan	B.S.527	612.15	
62	Vejae	B.S.49	606.27	
63	Hawa Singh	B.S.103	707.00	
64	MadanLal	B.S.188	167.20	

65	Neki Ram	B.S.338	31.10	
66	Balwan	B.S.386	610.80	
67	Ratan Singh	B.S.484	648.06	
68	Ramfal	B.S.275	701.00	
69	Mange Ram	B.S.142	43.00	
70	Ajit Singh	B.S.523	627.00	
71	Fate Singh	B.S.271	610.75	
72	Dalip Singh	B.S.603	37.00	
73	Rattan Singh	B.S.319	612.90	
74	Maya Chand	B.S.62	701.00	
75	Tirath	B.S.530	606.00	
76	Bhikhu Ram	B.S.462	649.41	
77	Rajander	B.S.577	608.40	
78	Jora Singh	B.S.602	660.30	
79	Rameshar Dat	B.S.410	828.50	
80	Amir Singh	B.S.100	617.65	
81	Bhal Singh	B.S.563	609.01	
82	Capt. Mahander Singh	B.S.432	611.65	

83	Om Parkash	B.S.350	700.00	
84	Jaidewa	B.S.373	609.00	
85	Chandgi	B.S.468	616.00	
86	Moji	B.S.335	614.00	
87	Tirath	B.S.448-A	710.00	
88	Ajit Singh	B.S.365	614.65	
89	Mehr Singh	B.S.154	607.90	
90	Baru Singh	B.S.453	49.77	

वक्तव्य

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Before I give details of the cases of specified consumers in villages under Mundhal Sub-Division of the Board for their being billed for amounts more than their normal monthly bills, I will be failing in my duty, if I do not state that the accusation made by the hob'ble for member, is incorrect and an exaggerated version of the facts. The hob'ble Member has mentioned that about 10000 consumers of 8 villages have beenissued highly exaggerated bills. The fact howeger is that total number of consumers in Mundhal Sub-division as on 31-1-83, is only 6761. Further

facts are that there are 51 villagers included in the jurisdiction of Mundhal Operation Sub-Division. The villagers Bass comprises of 4 Basties which are named individually by the hon'ble Member in his notice and in Addition there are 3 more villagers, there are only 226 consumers form these four villages who were issued bills for higher amounts over their normal bills for the reason that such consumers wee detected to have made unauthorised extensions of loads at their premises. The total number of such consumers in whole of the Sub-Division in 347. This number was detected out of 6761 consumers (category-wise split-up as given below) which falls under the Operattion Sub-Division.

Industrial	210
Agriculture	369
Commercial	184
Domestic	5934
Others	64
Total:	6761

Locality-wise total number of connections and number of consumers who were issued excessive bills is as under:

Sr. No.	Village	No. of domestic	No. of consumers issued excessive

		connections	bill
1.	Bass	590	146
2.	Mohalla	190	34
3.	Puthi	229	46
4.	Dhana Khurd	150	29
5.	Alakh Pura	150	49
6.	Rampura	70	14
7.	Garhi	124	29
		1503	347

Out of these 347 consumers, only 226 consumers belong to the villages which have been namedby the hob'ble Member in his Call Attention Notice.

Coming to the alleged excessive charges, it is clarified that these charges were made on account of unauthorised loads which were detected at the premises of such consumers. Hon'ble Members would agree that unauthorised load connected to the Board's installations is highly dangerous and exposes the constly equipment to the risk of total damage. In this case also a transfarmer of 100 KVA in village Basscosting Rs. 18000 approx, ogt burnt in 1/83 as a result of unauthorised load put onby the consumers theslelveswithout authorisation or even intimation ot the Board authorities while another transformer or 53 KVA the

coast of which is approximately Rs. 14000 got burnt in village Mohalla in 11/82. Further some of the meters installed at the premises of theconsumers to record ennergy consumption get burnt as a result of such unauthorised extensions. It was, therefor, highly imperative thatsuitable action is taken to curb such mal practices.

Coming to the assessment of additional amount, I am to state that, such assesment followed detection of unauthorised two BHP single phase motors installed by the consumers in their houses for grinding of flour and running chaffcutter.

The Board took notice of the growing practice of unauthorised extensions by the consumers and issued instructions in May, 1982 for recovering from consumes additional charges as the un authorised extension has adverse effect on the installation/supply system. Under these instructions, extra loads of the consumers who volumtarily disclosed the extent of extension were to be regularized. The consumers, has to pay additional charges for back period of 6 months and also seposit additional security so far as agricultural and industrial connections were concerned. In respect of domestic consumers, the loads wee to be regularised after deposit of additional security by the consumers for the enhanced loads. Regularisation of load in terms of these instructions was allowed upto the end of June, 1982. For any case, where the prescribed action was not taken by end June, 1982 the consumptionof the consumers was to be billed at double of his normal tariff in addition to enhanced one. The dates of voluntary disclosure wer extended by the Board first

upto 31-7-1982, and lastly inrespect of industrial and flat rate tubewell connections upto 15-11-1982. The voluntary disclosure in response to subsequent extension of date wee allowed to be regularised after payment of additional charges at therate of Rs. 35 per BHP per month. Where loads wee not dislosed, the rate of Rs. 50 per BHP per month was made applicable. While investigating the burning of the above mentioned transformers in the villages, the Sub-Divisional staff started detailed checking of loads and detected 2 H.P. motors un-authorisedly installed by consumers as explained earlier. The SDO treated the motive load as agricultural/industrial and levied charges at Rs 50 per H.P. per month for a back period of 6 months. Thus, the consumers with unauthorised load were charged in the bills Rs. 600/- in addition to the normal consumption bills.

In this connection, I am to further inform the hob'ble Members that due publicity to the instructions of the Board on the subject was given from time to time. As a result of this, total of 231 consumers, village-wise details as follows got gheir load regularised.

Sr. No.	Village	No. of unauthorised regulations upto 15.15.82
1.	Bass	111
2.	Mohalla	15
3.	Puthi	25

4.	Dhana Khurd	8
5.	Alakh Pura	61
6.	Rampura	
7.	Garhi	11
		231

Out of 231 consumers, 11 consumers belong to village Bass.

The additional charges were leived upon the consummers, in thebills dated 24/25-1-83. Large number of consumers made representations to the Xen. (OP) Divn. Hansi against the abnormally high bills. The Xen, on examining the bi9lls pointed out to the SDO that in the assessment of the charges, the instructions of the Board governing such cases has not been followed correctly as the unauthorised extension were on domestic connections, the consumers were liable to be charged enhanced security for the additional load and in additional their consumption was to be billed on double the tariff as applicable to domestic supply. He further advised the SDO to over-haul accounts of the affected consumers accordingly.

The SDO has accordingly withdrawn the charges incorrectly lived by him. The accounts of all the 226 consumers have to be overhauled afresh keeping in view the instructions of the Board. It sould thus be seen that the local

officer is already taking necessary action in the light of the instructions issued and the corrected bills are being rendered to the concerned consumers within the current month.

I would like to assure the House that there is not even the remotest intention of the Board to over charge any consumer muchless the farmer consumers who are being supplied electric power at subsidised rates, for the tubewells.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने मेरे काल अटें ान मो ान का जवाब देते हुए यह माना है कि वहां के एस0डी0ओ0 ने इन करैक्ट बिलिंग की है ओर अब उसने उन बिलों को विदड्रा कर लिया है तथा नए सिरे से बिल तैयार करके कंज्यूमर्ज को दिये जा रहे है । जो इन करैक्ट बिलिंग की गई है उसमे बोर्ड का कोई फाल्ट नही है वह रौंग बिलिंग एस0डी0ओ0 ने की है। उन बिजली के बिल्ज मे से कुछ बिल्ज उसने गलत तरीके से पैसा चार्ज करके ठीक भी कर दिये है। लेकिनजिन लोगों ने उस बारे मे विरोध किया, उन सबके बिलजी के कनैक ान काट दिये गये। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के बिजली के कनैक ान काट दिये गये है क्याउनके कनैक ान दोबारा जल्दी से जल्दी रैस्टोर कर दिये जायेंगे?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, जहां इस बात का ताल्लुक है कि एस0डी0ओ0 ने गलत तरीके से पैसे चार्ज करके लोगो के बिल ठीक कर दिये है, यह बात माननीय

सदस्य ने अपने काल अटैं ान मो ान केनोटिस मे नही पूछी है। अगर ऐसी बात है तो वे लिख करके हमारे नोटिस मे लाएं हम जरूर एक ान लेंगे । इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि वहां पर लोगों के बिजली के कनैक ान काट दिये गये है अगर ऐसी बात है तो उनके बिजली के कनैक ान दोबारा अव य जोड़ दिये जायेगे। मैं हाउस मे जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल सैक्टर और इंडस्ट्रीयल सैक्टर मे जहां पर भी अनअथोराइज्ड तरीके से एक्सटैं ान ली गई थी, वहां पर बिजली कानैक ान डिस कनैक्ट अव य हुआ था और जिन लोगो ने अन अथोराइज्ड तरीके से बिजली की एक्सटैं ानली थी, उनसे 50 रूपये पर मंथ के हिसाब से एडी ानल बिल चार्ज किये गये थे और उनकी सिक्योंरिटी ले ली गई थी। जो डोमोस्टिक सैक्टर है उस मे किसी भी जगह पर लोगों से ज्यादा बिल चार्ज नही किये गये है। उन गांवो मे उस एस0डी0ओ0 ने उन लोगो के बिजली के बिलों मे एग्रीकल्चरल सैक्टर के हिसाब से 50 रूपये एडी ानल एड कर दिये थे अब उसने वे सारे बिल विदड्रा कर लिये है और नए बिल बना दिए गये है। अगर उन गांवो मे किसी का बिजली का कनैक ान डिसकनैक्ट किया गया है तो वह दोबारा कनैक्टरक दिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, गांवों मे बिजली बोर्ड बपनी इनस्ट्रक ांज की पब्लिसिटी के लिये जो इ ितहार आदि फैंकता है उनको गांव के लोग आम तौर पर नही पढ़ते है जिसके

कारण उनको बाद मे नुक्सान उठाना पड़ता है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पब्लिसिटी के लिये इ ि तहार आदि फैंकने की बजाय कोई दूसरा ढंग निकाल जायेगा? जिसके द्वारा किसानों को बिजली बोर्ड की इनस्ट्रक ान की पूरी तरह से जानकारीहो सके और उनको बाद मे नुक्सान न उठाना पड़े। इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रौंग बिलिंग के बारे मे बिजली बोर्ड कंज्यूमर्ज को कोई नोटिस देगा कि तुम्हारे खिलाफ ये ये ि ाकायतें, तुम इन ि ाकायतों को दूर करो वरना तुम्हारे ऊपर डब्ल या ट्रिपल बिलिंग होगी। क्या आयंदा के लिये बिजली बोर्ड कंज्यूमर्ज को इस बारे मे कोई नोटिस देने का प्रोवीजन करेगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड को जो वालैंटरी डिसकलोजर की स्कीम थी उसके बारे मे न्यूज पेपर द्वारा और गांवा मे इ ि तहार आदि फैंकवा कर वाईड पब्लिसिटी दी गई थी। मैं अम्बाला ग्रिवैंसिज कमेटी की मीटींग मे गया था उस मीटिंग मे लोगो से मुझे यह ि ाकयत मिली कि बिजली बोर्ड की इनस्ट्रक ांज के बारे मे बहुत से लोगों को पता नही है और बिजली बोर्ड की इन्स्ट्रक ांज पब्लि ा हुए काफी समय गुजर गुजर चुका है। मैंने लोगों से यह ि ाकायत सुनने के बाद बिजली बोर्ड के चेयरमैन साहब से इस बारे मे बात की और मैंने कहा कि आप बिजली बोर्ड की इनस्ट्रक ांज रेडियों पर 10–15 दिन के लिये देहाती प्रोग्रामों मे दोबारा रीपीट करवाएं

ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतों कासामना न करना पड़े। हमने वरनैकुलर पेपरज मे दोबारा पब्लिसिटी की और डेट एक्सटैंड की। जहां तक नोटिस देने की बात है कि जो अन अथोराइज्ड एक्सटैं ान करता हुआ पकड़ा जाये उसको नोटिस दिया जाये, इस बारे मे मैं यह बताना चाहता हूं कि अन–अथोराइज्ड एक्सटैं ान के बारे मे जो चार्जिज होते है,ख वे बिजली के बिल मे भी लगा कर के भेजते है। इसके अलावा अन–अथोराइज्ड एक्सटैं ान की इंस्पैक्ट ान आदमी की मौजूदगी मे की जाती है और उस आदमी को यदि कोई एक्सप्लेनेभान देनी होती है तो वह उसी वक्त लिख करके या जुबानी दे सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जब उस अदमी केपास बिजली का बिल भेजा जाता है उस समय भी वह एतराज कर सकता है कि यह इन–फलेटिड बिल है। स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहूंगा कि उस एस0डी0ओ0 ने कोई बेईमानी नही की थी, बल्कि गलती की थी उस गलती के कारण उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि वहां के किसानों को कोई दिक्कत न हो।

श्रीमती करतार देवी, एम0एल0ए0 द्वारा सांपला विश्राम गृह मे एक महिला के अभिकथित बलात्कार के मामले मे जांच रिपोर्ट देने संबंधी (पुनरारम्भ)

श्रीमती बंसती देवीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि श्री आनन्द भार्मा कांग्रेस के वर्कर ने इसलिये उस मामले मे उस औरत को बदचलन बता कर केस बंद कर दिया गया, जिसके साथ उसने बलात्कार किया था। यदि आनन्द भार्मा की जगह कोई लोक दल का वर्कर होता तो इन्होंने उस औरत को अबला बता कर वर्कर को कोई न कोई सजा जरूर दे देनी थी। (ाोर एंव विघ्न) स्पीकर साहब,कितने अफसोस की बात है कि करतार देवी ने भी यह कह दिया कि वह इस मामले की जांच नही कर सकती। (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है। बहन जी, उन्होंने अपनी बात कहते हुए रेप का जिक्र किया है। (ाोर) मैं किसी की डियूटी लगा दूंगा।

श्रीमती बंसती देवीः यदि करतार देवी मे हिम्मत नही है तो मेरी डियूटी लगा दे या किसी और की डियूटी लगा दे।

श्री मंगल सैनः बहन करतार देवी ने जो बात कही है, उसको आप एक बार हाउस के नोलेज मे ला दे।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, करतार देवी जी ने यह कहा है कि यह केस रेप का है इसलिये मैं एक औरत होते हुए वहां पर जाकर ब्यान वगैरा कैसे ले सकूंगी। and expressed her inability to conduct the enquiry.

श्रीमती बंसती देवीः स्पीकर साहब, मैं पुलिस की बड़ी ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने उस औरत पर यह इल्जाम नही लगाया कि उसने आनन्द भार्मा का रेप किया था। (ाोर) स्पीकर साहब, आप कब तक वह इन्कवायरी करवा लेंगे ?

Mr. Speaker: Within 15 days I will get it enquired.

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के अभिभाशण का जवाब देते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने आ वासन दिया था कि जो टयूबवैल 80 फुट की गहराई पर लगे है उनके बिजली के रेट कम करके मंगलवार को बता दैंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैंने यह नही कहा था। मैंने यह कहा था कि मंगलवार को इस संबंध मे एक मीटिंग बुलवाई हुई है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि वह मीटिंग अब भी स्टैण्ड करती है।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान अब मैं विभिन्न कायों के बारे मे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत किये गये टाईम टेबल की रिपोर्ट पे ा करता हूं–

"The Committee met at 4.30 P.M. on Monday, the 14th March, 1983, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee, after some discussion recommended that the Business on 15th, 16th, 17th, 18th,. 21st, 22nd, 23rd. 24th and 25th March, 1983, be transacted by the Sabha as follows:-

Tuesday, the 15th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation adn adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
	3.	Papers to be laid on the Table of the House.
	4.	Discussion and Voting on Supplimentary Estimates (Second Instalment) for the year 1982-83.
Wednesday, the 16th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	General discussion on Budget for the year 1983-84.
Thursday, the 17th March,	1.	Questions Hour.

1983 (9.30 A.M.)		
	2.	Non-offcial Business.
Friday, the 18th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Resumption of General Discussionon Budget for the year 1983-84 and the reply by the Finance Minister.
Saturday, the 19th March, 1983	Off Day	
Sunday, the 20th March, 1983	Holiday	
Monday, the 21st March, 1983 (2.00 P.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Leave to introduce and introduction of Government Bills.

	3.	Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget.
Tuesday, the 22nd March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget.
Wednesday, the 23rd March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	The Haryana Appropriation Bill 1983 in respect of Budget.
	3.	The Haryana Appropriation Bill, 1983 in respect of the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1982-83
	4.	The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1983 alongwith in resolution of disapprovalof the Ordinance given by Shri Mangal Sein.

	5.	The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1983 alongwith the resolution of disapproval of the Ordinace given by Shri Mangal Sein.
	6.	The Punjab Ayurvedic and Unani practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1983.
Tuesday, the 24th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Reports of Assembly Committees and papers to be laid on the Table of the House, if any.
	3.	Non-offcial Business.
Friday, the 25th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under rule 15 regarding non-stop sitting.
	3.	Motion under rule 16 regarding adjourment of the Sabha

		sincdie.
	4.	Presentation of Reports of Assembly Committees and papers to be laid on the Table of the House, if any.
	5.	Official Resolution regarding raising the limit of loans by the Haryana State Electricity Board from Rs. 250 crores to Rs. 400 crores.
	6.	Legislative Business (1) The Haryana Forest Development Bill, 1983 alongwith the resolution of the dis-approval of the Ordinance given by Shri Mangal Sein. (2) The Maharshi Dayanad University Bill, 1983 alongwith the resolution of the dis-approval of the Ordinance given by Shri Mangal Sein.
	7.	Discussion on Motions under Rule 84 (1) “That the policy in regard to

		Tripartite talks relating to the Territorial disputes, and River Water issue and the stand taken by the State Government in this behalf, be discussed." (Notices given by Shri Mangal Sein and Shri Hira Nand Arya). (2) "That the day-to-day postponement of construction of Sutlej Yamuna Link canal in the Punjab Territory be discussed." (Notices given by Shri Hira Nand Arya)." (3) "That the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, which was laid on the Table of the House on the 9th March, 1983 be discussed." (Notices given by Shri Mangal Sein M.L.A.)."

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Speaker Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Repoet of the Business advisory committees.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट मे दी गई सिफारि ाों के साथ सहमत है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, कल बजट के पे ा हो जाने के बाद आपने अपने चैम्बर मे बी0ए0सी0 की मीटिंग बुलवाई थी। उस कमेटी के मैंबर सरकार की और से मुख्यमंत्री जी, पार्लियामेंट एफेयरज के मिनिस्टर और श्री हरपाल मीटिंग के समय भी कहा था कि विधान सभाके चुनाव के बाद पहली बार हम बजट सै ान मे इक्कठे हुए है। पहली बार इन्होंने दो दिन का सै ान बुलाया फिर तीन दिन का सै ान बुलाया था। अब भी ये 15 सीटिंगे करके ही सारा काम खत्म करना चाहते है। स्पीकरसाहब, इनको उस समय तो डर था लेकिन अब किस चीज का डर है ? स्पीकर साहब, जितने भी मैंबर यहां पर है उनका हरियाणा की एक करोड़ तीस लाख जनता के साथ सीधा संबंध है। जनता की कठिनाईयों को उन्होंने यहां पर कहना है और यही एक ऐसा फोर्म है जहां पर प्रत्येक सदस्य अपनी भिन्न भिन्न बातें रख सकता है। स्पीकर साहब, यह तीन हफते का समय बहुत कम है। जिस सयम पहली बार हम 7 तारीख को इक्कठे हुए थे उस समय भी मैंने कहा था कि समय बहुत कम है। आप समय बढ़ा लें। उस समय

सी0एम0 साहब ने कहा था कि गवर्नर एड्रैस के बाद बढ़ा लेंगे। अब मुख्यमंत्री महोदय अपनी प्रिाा के अनुसार कह देंगे कि मैंने ऐसा नही कहा। क्योंकि जो ये बातें कहते है, वह सभी सच्च होती है। और हामरी तरफ से यानी अपोजी ान की तरफ से जो बातें कही जाती है, वे सभी झूठी होती है। स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हाउस के अंदर प्रत्येक मैंबर अपनी अपनी बात कह सके। हाउस मे ही किसी बात पर खुले रूप से चर्चा की जा सकती है। यह अलग बात है कि इनको चर्चा पसंद नही है। पहली बार जब सै ान बुलाया गया था उस समय तो मार्जन बहुत कम था बाद मे इन्होंने परचेज से ब्रूट मैजोरिटी कर ली। (ाोर) स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि यह दुराग्रह छोड़ दें। आपको कोई खतरा नही है। आपके पासबहुमत है। ऐसी जल्दी क्यों है ? अगर आप दो दिन के लिये सदन मे और बैठ जायेंगे तो कौन सी मुसीबत आने वाली है। स्पीकर साहब, आप पिछला रिकार्ड देख लीजिये। बजट पर जनरल डिस्क ान के लिये दो दिन से ज्यादा टाईम मिलता रहा है। इनका यह कहना यह है कि गवर्नर एड्रैस पर जो कुछ कहा जा चुका है, इतना ही काफी हैं इसका मतलब तो यह हुआ कि आप के लिहाज से असैम्बली बैठनी ही नही चाहिए। अगर ऐसा है तो प्राईम मिनिस्टर से इतना सं ाोधन करवा दीजिए कि एक बार जो मुख्य मंत्री बन गया वह आजीवन मुख्य मंत्री बना ही रहेगा। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि सै ान के

लिये कम से कम दो दिन की एक्सटैं ान मिलनी चाहिए ताकि हम अपनी बात खुल कर हाउस मे कह सके।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने जो कुछ कहा है, मै। इसका समर्थन करता हूं। बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की जो रिपोर्ट सदन के सामने आई है, इसको देखने से पता चलता है कि अजट पर डिस्क ान के लिये दो दिन भी नही रखे गये। आप देखे, साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक क्वै चन आवर होता है, आधा घंटा काल अटैं ान एडमिट करने और रिप्लाई देने मे लग जाता है। इस तरह साढ़े 11 बज जाते है। साढ़े 11 बजे से डेढ़ बजे तक कुल दो घण्टे मिलते है बजट पर डिस्क ान के लिये और 18 तारीख को फिनांस मिनिस्टर साहब ने इस बहस का जवाब देना है। इसका मतलब यह हुआ कि सारे हाउस को बजट पर डिस्क ान करने के लिये केवल 3 घंटे ही मिलेगे। ये तीन घण्टे उस बजट पर डिस्क ान करने के लिये मिले है। जिसमे फिनांस मिनिस्टर साहब ने करोड़ों रूपये के टैक्स लगाए है। कुछ टैक्स तो इन्होंने कल की स्पीकच करते हुए लगाये, कुछ मोटर भाड़े खो चढ़ाने की भाक्ल मे लगाये और कुछ बिजली दर बढ़ाने की भाक्ल लगाये है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सारी चीजों पर डिस्क ान करने के लिये केवल तीन घंटे मिलते है जबकि हर मैंबर अपने हिसाब से अपनी बात हाउस मे कहना चाहता है। यह कहना कि पार्टी लीडर बोल लेंगे या दो चार मैंबर और बोल लेंगे, कहां तक उचित है।

हर माननीय सदस्य अपने हिसाब से अपनी कंट्रीच्यू ान करना चाहता है। इसलिये मेरी आप से गुजारि ा है कि तीन घंटे बजट पर डिस्क ान के कलये बहुत कम है। यह डिस्क ान नही के बराबर है। मुझे हैरानी है कि सरकार इतनी भाग दौड क्यों कर रही है, यह बात मुख्यमंत्री जी की मेरी समझ मे नही आती। इसके अलावा एंटी डिफैक ान बिल पर भी डिस्क ान होनी थी। इस हिसाब से तो उस पर डिस्क ान हो नही पायेगी। इसके अलावा डिमांडज पर डिस्क ान के लिये 2 दिन दिए गये है। बजट मे कम से कम 35–36 डिमांडज होती है। ये डिमांडज बेरियस डिपार्टमैंटस की होती है और इन डिपार्टमैंटस मे बहुत सी कमियां है, बहुत से लूप होल्ज है ओर इन कमियों को सदन के सामने लाने के लिये सब सदस्य बोलना चाहेंगे। 23 तारीख और इसके बाद जो आईटम्ज टेक अप की जायेगी, उन पर दस दस मिनट भी प्रत्येक आईटम को नही मिलते । 24 और 25 तारीख को वर्क बहुत ही ओवर लोडिड हो गया है। इस तरह एक आईटम को 10 मिनट भी नही मिलेंगे। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि सिटिंग आफ दी हाउस कम से कम दो दिन के लिये एक्सटैंड की जाये। डा0 साहब ने दो दिन की एक्सटैं ान का सुझाव दिया था लेकिन मैं कहता हूं कि अगर फैयर डिस्क ान करनी है तो कम से कम एक हफता के लिये हाउस एक्सटैंड कर दिया जाये।

श्रीमती चंद्रावती (बाढड़ा): जनाब स्पीकर साहब, हम अपनी बात और अपनी राय पहले ही कमेटी के सामने जाहिर कर

चुके है। जो कुछ मेरे साथी ने कहा है, मैं इसका समर्थन करती हूं। आप देखे, एप्रोप्रिए ान बिल, 23 तारीख को रखा है और उस दिन कितना क्राउडिड बिजनैस है ? इस बिल के लिये कम से कम एक दिन यानी चार घंटा भी नही मिलेगा। स्पीकर साहब, आप खुद ही इस बात पर विचार कीजिए। यहां तक नाम अाफि ायल डे के रैजोल्यू ान का ताल्लुक है, हमारे साथियों के साथ साथ ट्रैजरी बैंचिज के सदस्य भी बार बार इस पर बोल रहे है और आने वाले नान अफि ायल डे को ये भी बोलेंगे क्योंकि इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर दो दिन के लिये हाउस एक्सटैंड कर दिया जाये तो कोई फर्क नही पड़ेगा। होली के बाद दो दिन के लिये सै ान कर लीजिए। मुख्य मंत्री जी की तबीयत खराब है, छुट्टियों मे इनको आराम मिलेगा। इसलिये यह टाईम बहुत थोड़ा है, करोड़ों रूपये के बजट पर बहस करने के लिये 4 घंटे भी मिल रहे । इसके अलावा सप्लीमेंटरी डिमांड्स और बिजली बोर्ड की आईटम दोनों एक साथ ही रख दी है। बिजली बोर्ड वाली आईटम पब्लिक के लिये बहुत महत्व रखती है। एक बोर्ड बना रखा है जिसमे करोड़ों रूपये की हेरा फेरी है, इस पर बहुत से मैंबर बोलना चाहेंगे। इसलिये स्पीकर साहब, हमारी आपसे गुजारि ा है, प्रार्थना है और सबमि ान है कि सै ान को दो दिन के लिये एक्सटड कर दिया जाये, यह टाईम थोड़ा है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग

में जो कुछ हमने कहा और इन्होंने जो विचार रखे, वह आप के सामने की बात है। मैं उन दलीलों को रिपीट नही करना चाहता। स्पीकर साहब, 25 तारीख के बाद लगभग एक हफते की छुट्टियां हैं इनका यह कहना कि एक हफते के बाद दो दिन के लिये हाउस को बुला लिया जाये, इसका मतलब यह है कि स्टेट पर बड़ा भारी खर्चा पड़ेगा। जो मैंबरतीन हफते से यहां हाउस मे बैठे है। उनको भी अपनी कांस्टीच्यूएंसीज मे जाकर लोगो को टाईम देना चाहिए। इसके अलावा मुख्य मंत्री महोदय ने सरकार की तरफ से इनको परसुण्ड करने की कोि ा ा की थी कि अगर वाकई ही ये डिस्क ान के लिये ज्यादा टाईम चाहते है तो सरकार को कोई एतराज नही है इसके लिये एकप्रपोजल यह थी कि 17 तारीख को जो नान आफि ियल डे है, उसको आफि ियल डे मे कन्वर्ट कर लिया जाये क्योंकि जो यप्रस्ताव नान आफि ियल डे को डिस्कस होना है वह भी हमारी ही सदस्यों का प्रस्ताव है। दूसरी प्रपोजल यह थी कि 19 तारीख को सिटींग कर ली जाए और तीसरी प्रपोजल यह थी कि 26 तारीख को हाउस की पूरे दिन की सिटिंग कर कली जाये। ये तीन प्रपोजल यह थी कि 26 तारीख को हाउस की पूरे दिन की सिटिंग कर ली जाये । ये तीन प्रपोजल थी, सरकार इसके लिये तैयार थी और आज भी तैयार है, लेकिन इन तीनो बातों को हमारे आदरणीय मैंबर्ज ने माना है। इसका मतलब यह हुआ कि हाउस की फरदर एक्सटैं ान के लिये मैंबर नही चाहते। इन के मुंह से ''मैं न मानू, मैं न मानू'' की बात हनकल गई है। अगरये इस बात के लिये सीरियस है कि

डिस्क ान के लिये ज्यादा टाईम चाहिए तो आप ये तीनों दिन बे ाक युटिलाईज कर ले। इसके अलावा स्पीकर साहबख आपने यह भी कह दिया था कि 25 तारीख को सिटिंग का टाईम बढ़ा सकते है, लेकिन ये नही माने। इससे यह बात क्लीयर है कि आगे सै ान एक्सटैंड करने का सवाल नही है। आज भी अगर ये चाहे तो इन तीनो प्रपोजलज मे से कोई प्रपोजल मान जाये। अंत मे मैं हाउस से दुरख्वास्त करूंगा कि इस रिपोर्अ को एडौप्ट कर लिया जाये।

वाक आउट

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने आल्ट्रनेटिव प्रपोजल्ज दी थी और हम ने सबिमि ान की थी कि हमने पब्लिक सर्विस कमी ान की रिपोर्ट पर और मो ान अंडर रूल 84 पर बोलना है और इस के लिये तैयारी भी करनी होती है। इनको तो तैयारी की जरूरत नही क्योंकि इसके पास स्टाफ है, सैक्रेटरीज है और प्राईवेट सैक्रेटरीज है, जो सारी काम कर देते है, लेकिन हमें खुद तैयारी करनी पड़ती है। इसलिये इनकी बात को हमने स्वीकार नही किया। स्पीकर साहब, 25 तारीख के बाद तीन दिन की छुट्टी है और हमने इनको कह कि नैक्स्ट वीलक आराम से बोल सकेंगे। इन्होंने एक फारैस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया है जिसके लिये ये हमसे लाखो रूपये की

सैक ान मांग रहे है । इन्होंने लाखो रूपये खर्च करने के लिये फारैस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड को तो दिए है लेकिन मैंबरों को कुछ रूपये भी देने के लिये तेयार नही है। मैम्बर्ज को जनता ने चुन कर भेजा है। हम यहां पर पब्लिक की बात कहने के लिये है, इसलिये आपको और समय देना चाहिए। हम ही यहां पर पब्लिक की ग्रीवैन्सिज रख सकते है। (विघ्न)

Mr. Speaker: No I will put the motionto the vote of the House.

(At this stage all the Members of the opposition staged a walk-out.)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट मे दी गई सिफारि ाो के साथ सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब एक मुत्री साहब, टेबल पर कागज–पत्र ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir I beg to lay on the Table of the House—

1. The 14th Annual Report and Accounts of Haryana Financial Corporation for the year 1980-81, as required under sub section (3) of section 38 of the State Financial Corporation Act. 1951.

2. The 15th Annual Report and Accounts of Haryana Financial Corporation for the year 1981-82, as required under sub section (3) of section 38 of the State Financial Corporation Act. 1951.

3. The 13th Annual Report and Accounts of Haryana State Smal Industries and Export Corporation Ltd. for the year 1979-80, as required under section 619(a) of the Comapnies, Act. 1956.

4. The 14th Annual Report and Accounts of Haryana State Smal Industries and Export Corporation Ltd. for the year 1980-81, as required under section 619(a) of the Comapnies, Act. 1956.

5. The statement showing the loand raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1983 for which the State Government have stood guarantee for repayments under section 66 of the Electricitiy (Supply) Act, 1948.

6. The Annual financial Statement (Budget Estimates) of Haryana State Electricitiy Board for the year 1982-83, as requird under Section 61 of the Electricitiy (Supply) Act. 1948.

7. The Annual Administration Repoart of Haryana State Electricitiy Board for the year 1988-81, as requird under Section 75(1A) of the Electricitiy (Supply) Act. 1948.

8. The Annual Statement of Accounts of Haryana State Electricitiy Board for the year 1978-79, as requird under Section 69(4) & (5) of the Electricitiy (Supply) Act. 1948.

9. The Annual Administration Repoart of Haryana State Electricitiy Board for the year 1979-80, as requird under Section 75(i) of the Electricitiy (Supply) Act. 1948.

10. The Annual Statement of Accounts of Haryana State Electricitiy Board for the year 1979-80, as requird under Section 69(4) & (5) of the Electricitiy (Supply) Act. 1948.

वर्श 1982–83 के लिये सप्लीमैंटरी के लिये सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अब वर्श 1982–83 की सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स (सैकिंड इन्स्टालमेंट) पर डिस्क ान होगी।

जो मेंबर साहेबान चार्ज्ड आइटम्ज पर डिस्क ान करना चाहे, वे कर सकते है।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिये खड़ नही हुआ)

(ii) अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः पहली प्रैक्टिस के अनुसार और हाउस का समय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज एक साथ पढ़ी गई तथा पे ा की गई सभी डिमांडज एक साथ पढ़ी गई तथा पे ाक ी गई समझी जायेगीं माननीय सदस्य किसी भी डिमांड पर डिस्क ान8 कर सकते है लेकिन बोलते समय वह डिमांड का नम्बर बतादे जिसे ऊपर वे बोलना चाहते है। The demands will be put to the vote of the House after the consclusion of discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73334 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20029072 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 64090100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7624885 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13197498 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27666225 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26518000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.8-Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73074030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 252582740 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of

payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.10-Medical and public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14426403 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7276600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 56756096 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2451530 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17923120for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 77381990 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5251880 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.18-Animal Husbandary.

That a supplementary sum not exceeding Rs.795620 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.19-Fisheries.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10011680 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs.18893190 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.21-Communitiy Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10979900 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of

payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.22-Corporation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.46631095 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs.543180 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs.97089270 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.25-Loans and Advances by State Government.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker: since no hon. Member wants to speak, I will puyt the demands to the vote of the House.

Voices: All the demands be put together.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73334 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20029072 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 64090100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7624885 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13197498 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27666225 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.6-Finance.

The motion was carried.

वाक आउट

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर सहाब हमारे साथ सारी चीजों मे ज्यादती हुई है। रूलिंग पार्टी ने अन डेमोक्रेटिक रूख अपनायाहै। हमने एंटी डिफैक ान बिल रखा, वह रिजैक्ट कर दिया गया। श्री किताब सिंह एम.एल.ए. का मामला रखा था उसको आपने थोड़ा बहुत सम्भाला, लेकिन उस पर भी हमारी कोइ खास तसल्ली हनी हुई हमारे क्वै चनज भी ठीक से नही लगाये गये। हमारानौन आफि ियल रैज्योलू ान भी आद मे रख दिया गया और उसे भी हाउस मे आगे डिस्कस करने के लिये ये नही लाना चाहते है। अब बजट पर बोलने के लिये भी कोइ टाईम नही है। हमें मजबूर हो कर हाउस का बहिश्कार करनपा पड़ा। हम चाजहते है कि आपको पूरासहयोग दे लेककिन हमें पूरा समय नही मिल रहा हैं हम किसानों के बारे मे ,हरिजनों के बारे मे कुछ नही कर सके है। आप जानते है कि सरकार ने आम आदमी परीसेल्ज टैक्स बढ़ायाहै जजीया लगाया है। इसी प्रकार बिजली बोर्ड मे बड़ी भारी कुरप ान है। वहां पर बढ़ा भारी घपला हुआ है वे सारी बातै भी हमने कहनी है। बिजली ार्ड ने रिजैक्ट किये हुए गाजियाबाद की ईस्ट इंडिया कम्पनी के ट्रांसफार्मरज खरीदे है। 17 दिसम्बर के नवभारत अखबार मे भी यह खबर आयी हुई है। अगर आप टाईम बढ़ायेंगे तो ठीक है वरना हमें मजूबूर हो कर सै ान का बहिश्कार करना पड़ेगा।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। लीडर आफ दि अपोजी ान ने दो बातों परएतराज किया है जो सरकार के खिलाफ नही बल्कि स्पीकर साहब के खिलाफ कही है। एक तो इन्होंने कहा कि रीज्योलू ान नही आने दिया। दूसरे इन्होंने कह कि क्वै चन इस तरह से लगाये जाते है जो पूछ ही नही पाते है। ये दोनो बाते एक्सपंज की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्षः लीडर आफ दि अपोजी ान ने जो बाते यहां हाउस मे अभी कही है, वे सभी स्पीकर के खिलाफ कही हैं सरकार के खिलाफ नही कही। जिन बातो पर मैं रूलिंग दे चुका हूं उन्हे क्रिटिसाइज किया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टरका कहने का मं ाा यह है कि आपके सैंटीमेंटस को टच कियाजययेलेकिन लीडर आफ दि अपोजी ान का मं ाा यह नही है कि स्पीकर साहब के खिलाफ कुछ कहा जायें उनका तो केवल इतना मं ाा थाकि जो रैजयालू ान आया वह ऊपर नीचे हो गया। रूलिंग पार्टी के मैंबर का रैज्येलू ान एक तहसील के लिये थालेकिन उस पर सारे दिन कथा होती रही । हमने बार बार रिक्वैस्ट की कि इस रैज्योलू3 ानक ो भी अपने दउो लेतकिन उस पर डिस्क ान भाुरू होने के लिये यह नही माने। हमें अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार देने मे कोइ आपत्ति नही थी। आप चाहे सारे हरियाणा को बैक्वर्ड डिक्लेयर कर दे और उस

रैज्येलू ान को भी पास करवादे लेकिन जानबूझ कर उन्होनं हमारे रैज्योलू ान को समाप्त कर दिया जिसमे सारे हरियाणाका इन्ट्रैस्ट जुड़ा हुआ है। गवर्नमैंटर की टैक्टिकस है कि किसी तरह से हमारा रैज्योलू ान न आने पाये और तीनो नान आफि ायल दिनों मे उसी रैज्योलू ान पर बहस करायी जाये।

सैकण्डली जिस बात पर आपके सैटीमैंटस को टच करने की कोि ा ा की, वह है एण्टी डिफैक ान बिल । एंटी डिफैक ान बिल परहमने रूलिंग दे दी लेनिक हमने आपसे यह रिक्वैस्ट की कि आप रूलिंग देने से हपलेक हमारी बात एक बार तो सुन ले लेकिन आपने सुनना वाजिब नही समझा, खैर कोइ बात नही । हमारा कहने का मुछदा तो यह है कि यह जो सै ान हो रहा है इसके बारे मे जब बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट चल रही थी तब भी हमने कहा था। अगर आप साराकुछ मिनट टू मिनट कैलकूलेट करेंगे तो we will get only three hours for discussiojn on budget. इस समय मे से ही सरकार ने जवाब भी देना है। फिर हमारी साईड औरदूसरी साईड वालों ने भी बोंलना है। अपोर्जी ान को उसकी स्टैन्थ के हिसाब से टाईम मिलेगा। तीन घंटे मे से इनकोू एक घंटा ही समय मिलेगा क्योंकि सरकार की टूथर्ड मैजौरिटी है। इस एक घंटे मे लीडर आफ दि अपोजी ान बोलेंगी, वेरीयस ग्रुप्स के लीडर्ज बोलेंगे।इ कसे अलावा बाकी जो अपेाजीशन के मैंबरज साहेबान रह जाते है, उनमे से भी कईयों ने अपनी अपनी कांस्टीच्यूएड बड़ा ही सख्त हैं हमारी

आपसे अपीज है कि सारकर जो हमें गैंग करना चाहती है इसको कुछ समझाइये कि हमें बोलने का मौका दे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर सहाब, मैं आपसे एक मोहतबाना गुजारि ा करना चाहता हूं। इस हाउस को आप प्रिजाइड कर रहे है। आप इस हाउस के डैकोरम और डिगनिटी के कस्टोडियन है। हमारे राइटस और प्रिविलिज को भी आप ही वाच करते है। स्पीकर साहब, आप खुद एप्री ीयेट कर सकते है कि जहां डैमोक्रेसी मे ट्रेजरी बैंचिज का कन्ट्रोल होता है वहां अपोजीशन का भी कुछ रोल होता है। ब्रिटेन जोकि डैमोक्रेसी का मदर कंट्री है, मे अपोजी ान को बहुत ही डिगनीफाईड माना जाता है। स्पीकर सहाब, हमारी सबमि ान यही है कि हमें बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर आप ही हमें बोलने का मौका हनी देंगे तो हम कहां पर जाकर अपनी फरीयाद करेंगे, कौन साऐसाफोरम है जहां पर जाकर हमे अपनी फरियाद कर सकते है। आप ही देहिखये , क्लीन पब्लिक लाईफ के लिये एंटी डिफैक ान बिल लाना क्या बर्निंन्ग इ ू नही है? अखबारो को उठाकर देखिये। जिसने भी जूरिस्टस है और जितने भी सीरियसली थिंक करने वाले आदमी है, उकने लिये एक अड़ी भारी प्रोब्लम हो गयी है कि इस सैंचुरी मे इतनाकरैक्टर इरोजन हो गयाहै कि एक बादमी इलैक्ट तो किसी पार्टी से होता है, लेकिन दूसरे ही दिन किसी दूसरी पार्टी मे डिफैक्ट करके चला जाता है। जहां तक डिफैक ान के मामले का संबंध है ब्रिटेन मे अव्वल तो डिफैक ान होती ही

नही है, अगर होती थी है तो सैंचुरीज मे कोइ एक आध बार होती है। हरियाणा मे राज्यसभा की सीट के लिये हम3ए इलैक ान मे हुई क्रौस वोटिंग के बारे मे वीर प्रताप अखबार मे जो कुछ लिखा गया है, उन भाब्दों को पढ़ कर या सनुकर हमें तो बड़ी लज्जा आती है। हमारे मित्र तो फूल प्रूफ बन चुके है। इनको तो लज्जा आती ही नही है। हम एक तो डिफैक ान बिल पर बोलना चाहते है। सैकण्डली हम यह कहते है कि आप हमें बजट पर तो बोलने का पूरा मौका दे। इसके अलावा हरियाणाा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। अंडर रूल्ज हम उस पर डिस्क ान के लिये आपको रिक्वैस्ट कर सकते है। आज ही इसको टेबल किया गया है। हम इस पर भी मो ान देंगे।

श्री अध्यक्षः मैंने इसीलिये इसको डिले किया है।

श्री मंगल सैनः आपको हमको आपर्चूनिटी प्रावाईउ की है कि हम अगर मो ान देना चाहे तो दे सकें क्योंकि इसके अंदर 400 करोड़ रूपये का लेने की बात कर रहे है। हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक तरह से पैरेलल गवर्नमैंट है। इसका सब को पता है कि वहां परक्या हो रहा है और क्या नही हो रहा हैं अगर हम इस पर डिस्क ान करने के लिये प्रिपेयर हो कर नही आयेंगे तो हम कैसे और क्याबोलेंगे। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन सारी बातों को देखे! You are thoroughly correct, Sir. We have every regard for you. आप उन्हे मजबूर करिये ताकि हमें कोइ और कदम न उठाना पड़े। मेराकहनायह है कि ये तो

वैसे ही अपनी जिद पर अड़े रह है। इसलिये इनको समझाइयेगा। आज भी यह ऐसा कर सकते है कि एक और बीक के लिये सै ान का एक्सटैंट कर दे। We should not be gagged, Sir.

चौधरी ाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, एक बात वीरेन्द्र सिांह जी ने यह कही कि अगर तीन घंटे डिस्क ान हो तो दो घंटे ट्रेजरी बैचिज को मिलते है। ओर एक घंटा अपोजी ान को मिलता है। आपका रिकार्ड यह बोलता है कि 80 प्रति ात समय अपोजी ान को मिला है। हार्डली 20 प्रति ात समय ही हमें मिला है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं। जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने आयी, तो थोड़ी देर पहले ही इन्होंने अपने सारे आर्गूमैंटस ओर दलीले जितनीये दे सकते थे, दिये कि इनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही हैं यह वास्तव मे सही बात नही है। मुझे यह बात कहने के लिये समय तो नही लेना चाहिए। सच बत तो यह है कि हम तो तीन दिन फालतू हाउस की सिटिंग करने के लिये तैयार है लेकिन यह तो वैसे ही उंगली कटा कर भाहीद होने की बात कर रहे है। इसलिये मेरी आपसे अंत मे यह रिक्वैस्टहै कि पहले जो रिमार्क्स कहे गये है, से एक्सपंज कर दिये जाये।

श्रीमती चंद्रावतीः कौन से लफ्ज ?

चौधरी ाम ोर सिंह सुरजेवालाः जो आपने कहे थे।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, मैने आपकी तथा सैक्रेटेरियेट की भाान के खिलाफ कोई भी गलत लफ्ज नही कहे है और न ही मेरा ऐसा कहने का कोई मं ाा था। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: बात ऐसे है कि लीडर आफ दी अपोजी ान की काफी रिस्पौंसिबिलिटी होती है और आप अकसर कई दफा पता नही जान बूझकर या बगैर सोचे समझे कुछ कह जाती है। आपने 4–5 फिकरों मे जितनी भी बातें कही, उनमे से एक बात भी आपने गवनैमैंट के खिलाफ नही कही। आपने क्लीयर तौर पर यह कहा कि आपने एंटी डिफैक ान बिल हमारा काटा, रैज्योलू ान आपने हमारा काटा और आपने हमारे सवाल टिवस्ट कर लिये। (व्यवधान) आपने कहा कि हमारे बिल टिवस्ट किये गये है। फिर उसके बाद आपने यह कहा कि वरना.....। जहां तक मैडम, वरना वाली बात का संबंधहै, मैं किसी का हाथ तो पकड़ नही सकता, मैं किसी की जुबान भी नही पकड़ सकता, आपको पूरा अखितयार है कि जो कुछ आप करना चाहे, कर सकते है। मैं अपनी तरफ से इस बात की पूरी कोि ा ा करता हूं कि अपोजी ान कारे ज्यादा से ज्यादा टाईम किया जाये ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहने का मौका मिले और आप ज्यादा से ज्यादा गवर्नमैंट को क्रिटिीसाईज कर सके। जहां तक बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का संबंध है, मुझे सैक्रेटेरियेट कसे यह पता लगा थाकि इस कमेटी की मीटिंग तो 10–15 मिनट तक ही चलती है लेकिन मैने इसे आधे घंटे तक चलाया और इसके बाद भी मैंने आपसे और डाक्टर

साहब से बात की ओर रात के 10 बजे तक आपके टेलीफोन का इंतजार करता रहा। जहां तक टाईम की बात है, मेरायह सुझाव थाकि दोनो नान आफि ीयल डेज को आफीि ायलज डेज मे कन्वर्ट कर लिया जाये और दोनो सैचरडेज को भी सिटिंग कर ली जाये लेकिन उसके लिये भी आप तैयार नही हुए। गवर्नमैंट भी अपनी जिद पर अड़ी रही और आप भी अपनी जिद पर अड़े रहे। मेरे पास इसके सिवाय क्या चारा रहा गया था कि according to Rules of Procedure and Conduct of Business in the House, I should conduc the proceedings of the House. उसके बार आप वाक आउट कर गये। मैं देखता रहा कि भाायद आप वाक आउट करके फौरन ही आ जायेंगे। नैक्सट आईटम के लिये भी आप नही आये । मेरे पास इस बात के सिवाय कोइ चारा नही था कि मैं यह पूछूं कि क्या कोई मैंबर सहेबान कुछ कहना चाहता है। उन्होंने यह कहा कि इसे पास किया जाये। दोनों आइटम्ज पास हो जाने के बाद आप आये। इन हालात मे अगर आप मेरे ऊपर डाउट करें तो ठीक नही होगा। मैंतो दोनो की बातें सुनता हूं। बल्कि ट्रेजरी बैंचिज वाले यह कहते है कि मैं यहां पर अपोजी ान बैचिज की इमदाद करता रहता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर, आपकी नीयत परकिसी को भाक है ही नही। (व्यवधान व भाोर) सर, आपकी नीयत पर तो हम मे से किसी को भाक है ही नही। हम तो आपसे यह रिक्वैस्ट कर रहे है हक आप अपने गूड आफिसिज का इस्तेमाल करके गवर्नमैंट

को यह समझाइये कि यह हमारी बात को मान ले। आपकी नीयत परतो कोई भाक करता ही नही है।

श्री अध्यक्षः एक्चुअली जितना मैं समझा सकता था, मैंने समझाया है लेकिन अगर यह न मानें तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप रियल डैमोक्रेट है। आप ठीक ऐकोमोडेट करते है। आप कोई बात फील न करे।

Mr. Speaker: I have done to my capacity. जो कुछ मैं कर सकता था, वह मैंने किया है। अब मेरे पास कोई और चारा नही है।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, चेयरम को डिग्रेड करने की मेरे कभी इटैन ान नही होती। हम चेयरम को अटमोस्ट रिगार्ड हौर रिसपैक्ट देते है लेकिन गवर्नमैंट हमें एकोमोडैट करने के लिये बिल्कुल तैयार नही है। इस बारे मे हम आपका सरंक्षण चाहते है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने आपको रात को टैलीफोन किया था और आपने कहा था कि मैं जवाब दूंगी (ाोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चंद्रावतीः मेरा टेलीफोन ऐन्टैगल्ड हो गया। मैने आपको टेलिफोन करने की बहुत कोि ा ा की लेकिन टेलिफोन मिला ही हनी (ाोर एवं व्यवधान)।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, यहां का टेलिफोन सिस्टम बहुत ही खराब है। पंजाब मे उन्नीस लाइने है और हरियाणा विधानसभा मे सिर्फ पांच लाइनें है। जब भी लाइन मिलाने के लिये कहा जाता है तो कह देते है कि लाइने हैल्ड अप है। मैने सेक्रेटरी साहब को टेलिफोन सिस्टम खराब होने के बारे मे भी कहा है। बड़ी भारी प्रोबलम है। स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि हमें आपके खिलाफ कुछ नही कहना है। हम तो गवर्नमैंट के बारे मे कह रहे हैं। ये हमको अपनी मैजोरिटी केक बलबूते पर मजबूर कर रहे है कि हम यहां पर पार्टीसिपेट न कर सकें (ाोर एवं व्यवधान)।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इन्होंने जो कुछ कहना था वह कह दिया। अब ये हाउस का बहिश्कार करने की सोच रहे है। हाउस में दो जिहाई मैजोरिटी हमारी है और एक तिहाई मैजोरिटी इनकी है। आप रिकार्ड निकलव कर देख लीजिए दो तिहाई समय दिया गया है। और आगे भी अगर ज्यादा समय से लिये ये कहते है तो दो तिहाई समय इनको दे दीजिये और एक तिहाई हमको दे दीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इनकी बूट मैजोरिटी है and they are gagging us.

श्री हीरा नंद आर्यः हम विरोध मे वाक आउट करते है।

(इस समय विरोध पक्ष के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

वर्श 1982–83 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) पर मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now I will put the remaining demands to the vote of the House.

Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26518000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.8-Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73074030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 252582740 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.10-Medical and public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14426403 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7276600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 56756096 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2451530 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.14-Food and Supplies.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17923120for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 77381990 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5251880 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.18-Animal Husbandary.

That a supplementary sum not exceeding Rs.795620 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.19-Fisheries.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10011680 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs.18893190 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.21-Communitiy Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10979900 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of

payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.22-Corporation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.46631095 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs.543180 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs.97089270 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.25-Loans and Advances by State Government.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिये ऐडजर्न किया जाता है।

***11.43 बजे**

(तत्प चात सदन बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1983 प्रातः 9.30 बजे तक के लिये *स्थगित हुआ।)